News सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-212
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सुविचार

जो अंतर को देखता है,
बाह्य को नहीं,
वही सच्चा कलाकार है।

सिटी चीफ

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 07 नवम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

यूनाइटेड स्टेट्स खेल कर गया मिडिल ईस्ट में शांति लाने का ट्रंप का वादा, मुस्लिमों ने भी दिया अच्छा समर्थन, कमला हैरिस के 224 के मुकाबले ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट

अमेरिका में चला 'ट्रंप कार्ड'

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से यह साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। वोटों की गिनती में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में पीछे रह गई हैं। सबसे खास बात है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिला है। खुद मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी संख्या होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटरों का झुकाव ट्रंप की ओर देखने को मिला। मुस्लिमों का ट्रंप को अच्छा समर्थन मिलना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आमतौर पर अमेरिका में मुस्लिमों का समर्थन इसी पार्टी को रहा है। वहीं रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाली पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन अभी इजरायल-गाजा युद्ध की वजह से विश्व में जो हालात हैं, उससे ट्रंप को फायदा मिला है। ट्रंप ने चुनाव जीतकर अपनी पहली स्पीच में ही मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात एक बार फिर कही है। वे लगातार युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं मुस्लिमों को अच्छी लग रही है। जबकि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। ट्रंप की सरकार जाने के बाद जब जो बाइडन सत्ता में आए तो उन्होंने यह बैन हटाया। ट्रंप इस बार भी अपनी रैलियों में ट्रैवल बैन लगाने की लगातार बात करते रहे हैं। इसके बाद भी मिशिगन राज्य में ट्रंप को मिला सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चौंकाने वाला जरूर है।

2020 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन

डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार ऐतिहासिक जीत बहुत कुछ कहती है। यह दर्शाती है कि चुनाव में जिस कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया, वैसा असल में कुछ नहीं था। ट्रंप ने 2020 के अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया, जबकि डेमोक्रेट उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पिछले चुनाव में बाइडन के प्रदर्शन की बराबरी भी नहीं कर पाईं। ट्रंप ने जबरदस्त राजनीतिक वापसी करते हुए दूसरे कार्यकाल की राह सुनिश्चित की। ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे तभी खुलने लग गए थे, जब जार्जिया के उस किले को उन्होंने फिर से जीत लिया, जो 2020 में उन्होंने मामूली अंतर से गंवा दिया था। नार्थ कैरोलिना में उनकी जीत ने कमला हैरिस की हार की पटकथा लिख दी। पेंसिलवेनिया, एरिजोना, मिशिगन, विस्कान्सिन और नेवादा जैसे कड़े मुकाबले वाले राज्यों में भी हैरिस कुछ खास नहीं कर पाईं, जो उनकी जीत के लिहाज से बेहद अहम थे। अपनी 2016 की जीत के उलट इस बार ट्रंप पापुलर वोट्स के मामले में भी बाजी जीतने में सफल रहे। रिपब्लिकन पार्टी 1992 के बाद चुनाव में यह उपलब्धि दर्ज कर पाई है। स्वाभाविक रूप से ट्रंप ने जीत को शानदार करार देते हुए विजयी भाषण में समर्थकों से कहा, ह्यअमेरिका ने एक अभूतपूर्व एवं दमदार जनादेश दिया है।

दो महिलाओं को हराने का रिकॉर्ड

अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने दो महिलाओं को हराकर चुनाव जीता है। इस बार के चुनाव में उन्होंने कमला हैरिस को हराया तो इससे पहले 2016 के चुनाव में ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2024 और 2016 के अलावा कभी कोई महिला राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अलावा संसद के दोनों सदन के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव का इलेक्शन भी हुआ। इसमें सीनेट के चुनाव में रिब्लिकन ने बहुमत के आंकड़े 51 को पार कर लिया है तो वहीं, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में अभी बहुमत के आंकड़े 2018 से पीछे है। फिलहाल रिपब्लिकन को 193 सीटें मिली हैं।

एलन मस्क की मेहनत का बड़ा हाथ

इस चुनाव में अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति और उद्योगपति एलन मस्क ट्रंप के पक्ष में सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हुए। वे सोशल मीडिया कंपनी एक्स के भी मालिक है। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की उम्मीदवारी को अपना पब्लिक सपोर्ट किया बल्कि उनके पक्ष में तमाम रैलियां भी कीं। माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत के नीछे मस्क की मेहनत का बड़ा हाथ है।

भारत के पड़ोसी होंगे परेशान!

डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिनमें कनाडा और बांग्लादेश जैसी भारत विरोधी ताकतें भी हैं। दरअसल, ट्रंप की जीत से हमारे पड़ोसी देश परेशान हैं। यानी जो हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनकी हालत ट्रंप के आने से खराब होनी तय है। पहला पड़ोसी पाकिस्तान है। आतंक से उसकी पक्की दोस्ती हैं। जो बाइडेन उस पर मेहरबान थे। अमेरिका सख्ती कम कर रहा था, लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि साल 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खूब लताड़ा था। उसे अमेरिका से मिलने वाली मदद भी रोक दी थी। अब बात हमारे सबसे बड़े पड़ोसी चीन की। एलएसी पर 5 साल तक वह हमें आंख दिखाता रहा, लेकिन जो बाइडेन ने एक बार भी उसके लिए कुछ नहीं कहा। एक तरह से उसे मनमानी करने का मौका दिया, लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है। वे टैरिफ लगाकर चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की सौगंध खाकर राष्ट्रपति बने हैं। 2016 में भी उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ी थी। हमारा तीसरा पड़ोसी बांग्लादेश है, जिसकी सेना शेख हसीना का तख्तापलट कर चुकी है। इसके पीछे अमेरिका बताया जा रहा है। अमेरिका के दम पर ही बांग्लादेश भारत को पिछले कुछ दिनों से आंख दिखा रहा था लेकिन ट्रंप बांग्लादेश के होश ठिकाने लगाएंगे। वे पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा कर चुके हैं।

मध्यप्रदेश सागर, खरगोन, गुना और शहडोल विवि को सौगात

भवन निर्माण के लिए मिले 495 करोड़

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सागर, खरगोन और गुना सहित चार विश्वविद्यालयों में भवन निर्माण और पूंजीगत परियोजना के लिए 495 करोड़ राशि सशर्त स्वीकृति दी है। सागर, खरगोन और गुना में यह विवि इसी साल खोले गए हैं। जबकि, शहडोल में पहले से स्थापित पंडित शंभुनाथ शुक्ला विवि के लिए भी 45 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, सागर स्थित रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़, खरगोन स्थित क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ और गुना स्थित क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़, शहडोल स्थित पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के लिए 45 करोड़ राशि की भविष्य में पुनर्विलोकन की शर्त पर सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इन चार यूनिवर्सिटी के लिए करीब 495 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

टॉप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ेंगे सुपर-100 के छात्र - भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के मल्हाआश्रम स्कूल में सुपर-100 योजना के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों को अब देश के टॉप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए फाउंडेशन जैसी काम्पटीशन एक्जाम की तैयारी करेंगे। कोचिंग की शुल्क सरकार उठाएगी। वर्तमान में 300 छात्र-छात्राएं कोचिंग ले रही हैं। जेईई मेन्स में 50, जेईई एडवांस में 12 और नीट में 83 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है।

18 जिलों में लगेंगे अप्रेंटिसशिप मेले मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्किल डेवलपमेंट के लिए जबलपुर, रीवा और बालाघाट जोन के 18 जिलों में अप्रेंटिसशिप मेले आयोजित किए जाएंगे। शासकीय आईटीआई में प्रस्तावित इन मेलों में युवाओं को अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियों से जुड़कर स्टूडेंट्स न सिर्फ अपनी दक्षता का विकास करेंगे। बल्कि, रोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक बनेंगे। मध्य प्रदेश की

मोहन यादव सरकार ने सागर, खरगोन और गुना सहित चार विश्वविद्यालयों में भवन निर्माण और पूंजीगत परियोजना के लिए 495 करोड़ राशि सशर्त स्वीकृति दी है। सागर, खरगोन और गुना में यह विवि इसी साल खोले गए हैं। जबकि, शहडोल में पहले से स्थापित पंडित शंभुनाथ शुक्ला विवि के लिए भी 45 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, सागर स्थित रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़, खरगोन स्थित क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ और गुना स्थित क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़, शहडोल स्थित पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के लिए 45 करोड़ राशि की भविष्य में पुनर्विलोकन की शर्त पर सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। इन चार यूनिवर्सिटी के लिए करीब 495 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

टॉप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ेंगे सुपर-100 के छात्र भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के मल्हाआश्रम स्कूल में सुपर-100 योजना के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों को अब देश के टॉप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए फाउंडेशन जैसी काम्पटीशन एक्जाम की तैयारी करेंगे। कोचिंग की शुल्क सरकार उठाएगी। वर्तमान में 300 छात्र-छात्राएं कोचिंग ले रही हैं। जेईई मेन्स में 50, जेईई एडवांस में 12 और नीट में 83 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है।

18 जिलों में लगेंगे अप्रेंटिसशिप मेले मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्किल डेवलपमेंट के लिए जबलपुर, रीवा और बालाघाट जोन के 18 जिलों में अप्रेंटिसशिप मेले आयोजित किए जाएंगे। शासकीय आईटीआई में प्रस्तावित इन मेलों में युवाओं को अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियों से जुड़कर स्टूडेंट्स न सिर्फ अपनी दक्षता का विकास करेंगे। बल्कि, रोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक बनेंगे।

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, आर्टिकल 370 पर भिड़े बीजेपी और सत्ता पक्ष के विधायक

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार(7 नवम्बर) को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सब कुछ बारमूला के सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 को वापस बहाल करने वाला बैनर दिखाया। इससे सदन में बैठे बीजेपी के नेता भड़क उठे। बीजेपी के नेता सुनील शर्मा अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और इस बैनर को लहराने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। बाद में मार्शलों को बुलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खामोशी के साथ सदन में बैठे नजर आए। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब आर्टिकल 370 किसी भी नौबत पर वापस बहाल नहीं होगा। विवाद बढ़ने पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा में पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35 ए को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। इस बात पर भी बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया। बता दें कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी चुनावी घोषाणापत्र में जम्मू-कश्मीर को फिर से विशेष दर्जा देने और आर्टिकल 370 को बहाल करने का वादा किया था। बीजेपी के जम्मू कश्मीर केअध्यक्ष सत शर्मा ने क्या कहा बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष ने असंवैधानिक तरीके से बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में आर्टिकल 370 और 35 ए को बहाल करने से जुड़ा था। इस विधेयक को एक ऐसी स्थिति में पारित किया गया जब विधानसभा में हंगामा हो रहा था। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस आर्टिकल को रद्द करने का फैसला एकपक्षीय था। जबकि, इस आर्टिकल को रद्द करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई थी।जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने बीजेपी विधायकों को मार्शल की मदद से विधानसभा से बाहर करने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि, कल भी आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव पारित होने से पहले बीजेपी के विधायकों को मौका दिया गया था। हालांकि, बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। ऐसे में यह कहना कि 370 से जुड़े प्रस्ताव को गुपचुप पारित कराए जाने का आरोप गलत है।

विद्यालक्ष्मी योजना के तहत मेधावी छात्रों को मिलेगा सस्ता लोन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद है कि मेधावी छात्रों की पढ़ाई में अड़चन न आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ एजुकेशन लोन में मिलेगा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपएतक का शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर लिया जा सकेगा। वैष्णव ने बताया कि मेधावी बच्चे बैंकों से लोन उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई के लिए लोन ले सकेंगे। इस योजना के प्रभाव से अब पैसे की कमी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी। शिक्षा ऋण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करेगा। वैष्णव ने बताया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समर्थन-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण लिया जा सकेगा। वैष्णव ने बताया कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है। इन परिवारों के छात्रों की पढ़ाई के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3त्न ब्याज अनुदान मिलेगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार 75त्न क्रेडिट गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि मिशन मोड तंत्र शिक्षा के विस्तार को सुगम बनाएगा। मेधावी बच्चों की पढ़ाई के अलावा कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं। वैष्णव ने बताया कि खाद्यान्न की खरीद में एफसीआई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी देने का निर्णय लिया है।

पीएमएलए से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सरकारीकर्मी और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी इजाजत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ उनकी पब्लिक ड्यूटी के दौरान हुए कथित अपराध के मामले में उन पर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत तहत केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा-197 (1) के तहत प्रावधान है कि सरकारीकर्मी के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का यह प्रावधान पीएमएलए केस में भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दी थी। जिसमें हाई कोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ बिना स्वीकृति के केस चलाए जाने को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में ईडी ने सरकारी अधिकारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भूमि आवंटन में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और संपत्तियों का अवमूल्यन किया। उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर छूट प्रदान की और कथित तौर पर पूर्व सीएम से जुड़ी संपत्तियों को लाभ पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने साजिश रची जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। यह मामला जब हाईकोर्ट के सामने आया तब आईएएस अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया वह अपने आधिकारिक क्षमता के अधीन लिया और ऐसे में उन पर केस चलाने से पहले सीआरपीसी की धारा-197 के तहत सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी जरूरी है। वहीं ईडी ने कहा था कि पीएमएलए एक विशेष एक्ट है और ऐसे में इस मामले में किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है।

मप्र के 55 जिलों में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़े, भोपाल में फिलहाल रोक

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 55 जिलों में 3500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए हैं। यह बढ़ोतरी कलेक्टरों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर की गई है, जिनमें प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ाकर सरकार की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की गई है। कलेक्टरों ने 1 लाख 12 हजार लोकेशंस के लिए प्रस्ताव भेजे थे, जिन्हें केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंदौर में सबसे ज्यादा 3त्न की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, भोपाल जिले में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का फैसला फिलहाल होल्ड पर है। यह निर्णय डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के हस्तक्षेप के कारण लिया गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी ने प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने का विरोध किया था। इसके बाद, भोपाल क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने भी इस फैसले का विरोध किया और अपनी बात सांसद और विधायक को पत्र के माध्यम से रखी। राज्य के बाकी हिस्सों में, विशेष रूप से बड़े महानगरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 3त्न तक की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम राज्य सरकार के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और रियल एस्टेट सेक्टर को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इंदौर में पहली बार साल में दूसरी मर्तबा गाइडलाइन बढ़ी है। प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। इसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। दाम बढ़ने के साथ ही लोगों को अधिक बैंक लोन मिल सकेगा। सरकार को भी ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। साल 2024-25 में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ गई है।

साल में दूसरी बार 469 लोकेशन पर बढ़ी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर में संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है। इसकी वजह यह है शासन के निर्देशानुसार जिले में साल में दूसरी बार गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की गई है। जिले में 469 लोकेशन पर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इंदौर में ऐसा पहली बार हुआ है कि साल में दूसरी मर्तबा गाइडलाइन बढ़ी है। गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। इसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। दाम बढ़ने के साथ ही लोगों को अधिक बैंक लोन मिल सकेगा। सरकार को भी ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। दरअसल, साल 2024-25 में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ गई है। प्रस्ताव को भोपाल भेजा गया था। इसे बुधवार को मंजूरी दे दी गई। पिछले चार दिन में आए 26 दावे-आपत्तियों में से पंजीयन विभाग ने 8 को मान्य किया। इनमें दो लोकेशन पर बढ़ाई गई प्रस्तावित गाइडलाइन को कम किया है, तो एक में बढ़ाया है।

105 नई कॉलोनियों को गाइडलाइन में जोड़ा

5 हजार लोकेशन में से 469 लोकेशन/क्षेत्र/कॉलोनी में गाइडलाइन बढ़ाने को जिला मूल्यांकन कमेटी ने मंजूरी दी थी। 105 नई कॉलोनियों/टाउनशिप को भी गाइडलाइन से जोड़ा गया है। कुल 580 लोकेशन नई गाइडलाइन से प्रभावित होंगी। इससे पहले अप्रैल में 2300 से ज्यादा लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई गई थी। बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक भोपाल में हुई। यहां इंदौर के प्रस्ताव को

जस का तस स्वीकार कर लिया गया। बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा 31% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है। तैयार किया गया है। यहां 0 से 31 प्रतिशत की बढोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं 105 नई कालोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है। जिला मूल्यांकन समिति ने बढौतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

बैठक में हुआ अंतिम निर्णय

वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू, दीपक कुमार शर्मा और अन्य सब रजिस्ट्रार ने दावे-आपत्तियों का निराकरण किया। विभाग ने पहले 469 लोकेशन पर दर्ज वृद्धि और 105 नई कॉलोनियों को जोड़ने का प्रस्ताव बनाया था। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिलकर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव फाइनल किया और उसे महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय को भेजा था। उप महानिरीक्षक पंजीयक बालकृष्ण मोरे के मुताबिक राज्य शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, इसलिए इंदौर-उज्जैन संभाग के सभी जिलों के प्रस्ताव भेजे गए। अंतिम निर्णय बुधवार को हुई बैठक में हुआ।

शून्य से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि 112 लोकेशन पर

इस बार जो प्रस्ताव इंदौर जिले का तैयार हुआ था, उसमें शून्य से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि 112 लोकेशन, 11 से 20 प्रतिशत में 190, 21 से 30 प्रतिशत में 77 क्षेत्र और 90 में 31 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। डॉ. नायडू ने बताया कि 26 आपत्तियों-सुझाव में से 6 सुझाव नई कॉलोनियां को जोड़ने के थे। इस तरह नई कॉलोनियां जो गाइडलाइन में शामिल की गईं, उनकी संख्या 111 हो गई है। दो कॉलोनियों में प्रस्तावित गाइडलाइन में आंशिक कमी की गई है। इसी तरह एक कॉलोनी में गाइडलाइन वृद्धि का प्रतिशत कम किया।

भोपाल में जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव अभी रोका

राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर जाता नजर आ रहा है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बुधवार को वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के अंतर्गत जमीनों के प्रस्तावित मूल्य वृद्धि को जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर लागू करने का आग्रह किया। आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री देवड़ा को जमीनों के बढ़े हुए भाव को लेकर लिखित शिकायत भी की। अब जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद ही कलेक्टर गाइडलाइन पर अंतिम मुहर लगेगी। जनप्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक के बाद ही भोपाल में जमीनों के बढ़े हुए दामों को लेकर फैसला होगा। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि वित्तमंत्री ने भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। शहर में 243 स्थानों पर जमीन की कीमतें बढ़ाना जनहित में नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री को पहले पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। सांसद ने यह भी बताया कि वे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड और जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य एवं विधायक भगवानदास सबनानी से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबनानी ने अपने क्षेत्र की 13 जगहों पर बढ़ाई गई दरों पर पुनर्विचार का सुझाव दिया था। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि साल में दूसरी बार जमीन की दरों में वृद्धि से सरकार की योजनाओं और नीतियों पर असर पड़ता है। लगातार बढ़ रही जमीन की कीमतें न तो राजस्व में वृद्धि कर रही हैं, न ही निवेश आकर्षित कर रही हैं। सांसद का मानना है कि जमीन की कीमतों को स्थिर रखा जाए ताकि मध्य प्रदेश में निवेश का माहौल बना रहे। बेहतर होगा रेट ना बढ़ाई जाए।

इंदौर से 16 दिसंबर को रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन

रामेश्वरम, तिरुपति और कन्याकुमारी देख सकेंगे पर्यटक

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। देश के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए रेल विभाग ने देखो अपना देश योजना के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की संचालन शुरू किया है। इसके तहत इंदौर से दक्षिण भारत के लिए इंदौर को भी एक ट्रेन मिली है। यह ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी, जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी के अलावा अन्य स्थलों की सैर कराएगी। यह ट्रेन मदुरई, त्रिवेंद्रम भी जाएगी। इसका संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड कर रहा है। यात्रा में कई सुविधाएं मिलेगी। यह ट्रेन इंदौर के अलावा देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, शाजापुर, इटारसी, बैतूल और नागपुर स्टेशनों से जाएगी और प्रदेश के लोग इन स्टेशनों से सवार हो सकते है।

नौ दिन और 11 दिनों तक की यात्रा के दौरान दक्षिण भारत के पर्यटक स्थलों की सैर कराएगी।

9 रात और 11 दिन की इस यात्रा

नौ रात और 11 दिनों की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंदम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। ट्रेन की स्लीपर श्रेणी का प्रति व्यक्ति किराया 18 हजार 200, थर्ड एसी श्रेणी का 29 हजार 500 और सेकेंड एसी श्रेणी का किराया 39 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि इस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी का किराया 18 हजार, थर्ड एसी का 29 हजार और सेकंड एसी का 39 हजार रुपये रहेगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को रुकने, सड़क परिवहन, बसों

से पर्यटक स्थलों तक जाने की सुविधा दी जाएगी। यह ट्रेन विशेष एलएचबी रैक के साथ चलेगी। इस यात्रा के लिए कई यात्रियों ने बुकिंग कर दी है।

ये सुविधाएं मिलेंगी

विशेष एलएचबी रैक वाली इस ट्रेन में लोगों को आरामदायक रेल यात्रा, ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और अच्छी बसों से दर्शनीय स्थलों की यात्रा, रुकने की व्यवस्था, टूर एस्कॉर्ट, यात्रा बीमा, सुरक्षा और हाउस कीपिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या इंदौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म-एक स्थित केंद्र पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं।

रीवा-इंदौर के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू

रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए इंदौर और रीवा के बीच स्पेशल सिंगल ट्रिप ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रीवा-इंदौर- रीवा के बीच एक-एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 02186/02185 रीवा-इंदौर-रीवा स्पेशल ट्रेन, रीवा से बुधवार को शुरू हो गई है और इंदौर से गुरुवार को एक-एक फेरे के लिए चलेगी। यह गाड़ी रीवा से चलकर सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संतहिरदा रामनगर और उज्जैन होकर इंदौर स्टेशन पर पहुंचेगी। इंदौर से यह दोपहर 1 बजे रवाना होगी। उज्जैन 2.25 बजे, शाम 5.20 बजे संत हिरदाराम नगर, शाम 5.50 बजे भोपाल पर हॉल्ट लेगी। रानी कमलापति स्टेशन पर शाम 6.07 बजे, नर्मदापुरम 7.13 बजे, इटारसी जंक्शन 8 बजे, पिपरिया 9.10 बजे, नरसिंहपुर 10.23 बजे, जबलपुर 11.40 बजे पहुंचकर अगले दिन कटनी मध्य रात्रि 1 बजे, मैहर 1.53 बजे, सतना 2.35 बजे पहुंचकर मध्य रात 3.45 बजे रीवा पहुंचेगी।

मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनाने का ठेका दूसरी बार भी निरस्त

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए दूसरी बार जारी टेंडर इंदौर नगर निगम ने दूसरी बार भी निरस्त कर दिया है। इन सड़कों के लिए अब तीसरी बार टेंडर जारी किए जाएंगे। निगम ने इन सड़कों के लिए चार अलग-अलग पैकेज में टेंडर जारी किए थे। पहली बार जारी टेंडर चार निर्माण एजेंसियों के आपस में संगमत होकर टेंडर डालने की आशंका के चलते निरस्त कर दिए गए थे। इसमें इन कंपनियों ने सड़कों को बनाने के रेट नौ प्रतिशत तक ज्यादा दिए थे। दूसरी बार जारी टेंडर इसलिए निरस्त कर दिए गए क्योंकि इस बार कंपनियों ने सड़क बनाने के रेट छह से सात प्रतिशत तक ज्यादा दिए हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि तीसरी बार टेंडर आमंत्रित करने पर आर्थिक लाभ हो सकता है और दर और कम हो सकती है। केंद्र सरकार ने इंदौर की 23 सड़कों को बनाने के लिए 468 करोड़ रुपए नगर निगम को आवंटित किए हैं। वहीं निगम का दावा है कि सिंहस्थ से पहले इन सड़कों का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि इंदौर होकर उज्जैन जाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। इधर सड़कों के टेंडर दूसरी बार निरस्त होने पर कांग्रेस मैदान में उतर आई है। उसने गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं नगर निगम के जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर के मुताबिक पहली बार के मुकाबले दूसरी बार के टेंडर में सड़कों की लागत कम हुई थी। हम तीसरी बार टेंडर बुला रहे हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि दूसरी बार के मुकाबले भी कम लागत पर टेंडर आएंगे। इससे नगर निगम को आर्थिक लाभ होगा।

ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। इस बार भी देशभर की एमएस और एमडी की सीटों को भरने के लिए 4 राउंड होंगे, जिसमें से 3 मुख्य राउंड रहेंगे और चौथा राउंड ऑनलाइन स्ट्रे वेकेंसी भरने के लिए होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर ऑल इंडिया कोटे के साथ-साथ स्टेट कोटे की काउंसलिंग का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि ये शेड्यूल प्रदेश की डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर अभी जारी नहीं किया गया है। देशभर से हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट पीजी देते हैं। पिछली बार 2 लाख 28 हजार छात्रों ने नीट पीजी दी थी। काउंसलिंग के चार राउंड में से पहला राउंड 8 नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत 17 नवंबर तक पहले चरण की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करना होगी। सीट अलॉटमेंट 18 और 19 नवम्बर को होगा । रिजल्ट 20 को जारी होगा। कॉलेज में रिपोर्ट करने की आखिरी तारिख 27 नवंबर है।

एमवायएच में मॉलेक्युलर लैब...गर्भ में होगी सिकल सेल एनीमिया की पहचान

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। अब एडवांस मॉलेक्युलर लैब की जांच में पता चल जाएगा कि गर्भस्थ शिशु को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा इसकी जांच के लिए मॉलेक्युलर लैब बनाई जा रही है। 15 नवंबर को इसका शुभारंभ हो सकता है। प्रदेश में इंदौर के अलावा यह लैब भोपाल में भी बन रही है। इस लैब के लिए केंद्र से 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। एमवाय अस्पताल में ब्लड बैंक के पास यह मॉलेक्युलर लैब की यूनिट बनाई जा रही है। डब्ल्यूएचओ के कन्सलटेंट्स भी इसके लिए एमवायएच आकर इसे देख चुके हैं। इसकी जांचों के लिए मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया भी हो चुकी है।

जल्दी हो सकेगा इलाज

मॉलेक्युलर लैब का 15 नवंबर को शुभांरभ हो सकता है इसलिए इसे बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। एनीमिया की जांच करने वाली मशीनों के आने तक माइक्रोबायोलॉजी विभाग की मदद से इसकी जांच की जाएगी। डीन डॉ. संजय

दीक्षित के मुताबिक इसका फायदा होगा कि जन्म से पहले ही बच्चों में सिकल सेल एनीमिया का पता लगाया जा सकेगा। इससे इलाज जल्द हो सकेगा। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि उद्घाटन से पहले ही लैब का काम पूरा कर लें।

मॉलेक्युलर लैब से होंगे कई लाभ

मॉलेक्युलर लैब की अलग यूनिट स्थापित होने से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, गर्भस्थ शिशु की जांच, रेड सेल एक्सचेंज प्रोग्राम आदि सुविधाएं मरीजों को मिलने लगेंगी। वर्तमान में इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट से पीसीआर और एचपीएलसी मशीन खरीदी जाएगी। मॉलीक्युलर लैब में सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को इलाज की आधुनिक सुविधा दी जाएगी। सिकलसेल रोगियों का बोनमेरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। लैब में बीमारी से पीड़ित महिला के गर्भ में भ्रूण की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश मॉलेक्युलर लेवल पर की जाएगी कि बच्चा सिकल सेल से ग्रस्त तो नहीं है। इसमें रेडियोलॉजी, प्रसूति, शिशु रोग, मेडिसिन विभाग आदि से समन्वय कर आधुनिक प्रकार की जांच की जाएगी। मरीजों का इलाज मुफ्त में होगा और शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है यह बीमारी

सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ज्यादा है। सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स का आकार टेढ़ा हो जाता है। इससे खून की कमी, जोड़ों में दर्द सहित कई समस्याएं होने लगती है।
- यदि माता-पिता दोनों को सिकल सेल बीमारी है तो उनके बच्चों को इसके होने की आशंका अधिक होती है। इस बीमारी का कोई स्थाई इलाज नहीं है।

इंदौर डिवीजन में झाबुआ, आलीराजपुर, खंडवा, खरगोन आदि जिलों से मरीज रैफर होकर इलाज करवाने इंदौर आते हैं। एमवाय अस्पताल में 800 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जबकि कई व्यस्कों का भी इलाज चल रहा है। मप्र में जनसंख्या का 21% हिस्सा इन जनजातीय समूहों का है। इनमें सिकल सेल एनीमिया के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में अब तक 33 जिलों में सिकल सेल एनीमिया के 20,526 मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते फिलहाल इंदौर और भोपाल में सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए मॉलेक्युलर लैब शुरू की जा रही है। भारत में 2047 तक इसे जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंगल कॉलम

इंदौर फिर आएंगे विदेशी मेहमान ईएजी प्लेनरी दल की मीटिंग 25 से

इंदौर। ईएजी प्लेनरी दल (यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स) की पांच दिनी कॉन्फ्रेंस इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक होगी। पिछले साल हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन, खेलो इंडिया, जी-20, ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के बाद फिर यह एक इंटरनेशनल स्तर का आयोजन होगा। हालांकि इसमें सिर्फ 150 डेलीगेट्स ही आएंगे। इसके मद्देनजर संभागायुक्त दीपक सिंह ने मंगलवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। संभागायुक्त ने ईएजी प्लेनरी दल के प्रतिनिधियों और ऑब्जरवर्स के आगमन से लेकर पूरे भ्रमण कार्यक्रम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। एयरपोर्ट पर स्वागत सहित अन्य सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, एडि. सीपी अमित सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह आदि मौजूद थे।

सड़क पार करते समय दो लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

इंदौर। इंदौर के तेजाजी नगर में सिल्वर स्प्रिंग के पास मंगलवार रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि उसका दूसरा साथी घायल हो गया है। बताया गया है कि दोनों साथी सड़क पार कर रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। तेजाजी नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुनील (45) पुत्र जगदीश कटिजा निवासी सिल्वर स्प्रिंग और उसके साथी नाना भाया को रात करीब 10 बजे लगभग टाउनशिप के पास एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान सुनील काफी दूर जाकर सड़क पर गिरा। जबकि नाना भाया नजदीक में कच्चे रोड़ पर गिर गया। हादसे के दौरान गंभीर हालत में सुनील को एमवाय अस्पताल में ??????भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई। वही नाना का इलाज जारी है। परिवार के लोगो ने बताया कि सुनील अपने दोस्त नाना का पत्थर मुंडला इलाके में मकान खाली करवाने गए थे। पैदल सड़क पार करते समय ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी, हम्माली के काम से जुड़े थे, सुनील के परिवार में दो बेटे और एक बेटी है, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।

एमवाय हॉस्पिटल में डॉक्टर से विवाद करने वाले युवक को पुलिस को सौंपा

इंदौर। एमवाय हॉस्पिटल में बुधवार को डॉक्टर और अटेंडर के बीच विवाद हो गया। मरीज को वायरल होने के चलते तीन दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। मरीज के अटेंडर का आरोप है कि इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में डॉक्टर चेतन से बात की। अटेंडर के मुताबिक इलाज की बात पूछने से नाराज डॉक्टर के साथी आए और मारपीट करने लगे। अटेंडर युवक को चौकी से पुलिस बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। मामले से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस अटेंडर युवक को ले जा रही है। युवक वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे गाली दी गई और पीटा गया। पुलिसकर्मी उसे चौकी पर ले गए और वहां बैठा दिया। मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है।

प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या करने वाला हिस्ट्रीशीटर पुलिस की गिरफ्त में

इंदौर। महिला की हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर बदमाश को गांधीनगर पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आरोपी की पिछले छह माह से तलाश कर रही थी। आरोपी ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक खजराना क्षेत्र निवासी रुखसाना की सुपर कोरिडोर क्षेत्र में आरोपित जावेद अब्बासी निवासी जूना रिसाला ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी। आरोपी रुखसाना को बाइक पर बात करने के बहाने ले गया था। घटना के बाद जावेद फरार हो गया। पुलिस ने कई जगह दबिश दी लेकिन वह हाथ नहीं आया। अब पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नागपुर जा रहे प्लेन में खराबी, फ्लाइट में बैठे यात्रियों को उतारा

इंदौर। इंदौर से नागपुर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को उड़ान भरने से पहले बिगड़ गया। तकनीकी इंजीनियरों ने जांच के बाद कंपनी को कहा कि विमान उड़ान नहीं भर सकता। इसके बाद विमान में सवार यात्रियों को वापस लाउंज में भेजा गया। विमान को सुधारने के बाद सुबह करीब आठ बजे जाने वाला विमान सुबह 11 बजे बाद रवाना हुआ। इस कारण आगे की उड़ान भी लेट हुई। इंदौर से नागपुर के लिए इंडिगो का यह विमान रोज सुबह 7.55 बजे उड़ान भरता है। बुधवार को इस विमान में 71 यात्री सवार थे और विमान रनवे पर जाने की तैयारी कर रहा था, इस बीच

81 वर्षीय डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम के भरतनाट्यम ने सभी का मन मोह लिया

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। कला या अन्य सभी विधाओं को सीखने के लिए शिष्य में शरणागति का भाव जरूरी है। नवधा भक्ति, नारद भक्ति सूत्र सहित शास्त्रों में भी शरणागति की विशेष महिमा बताई गई है। शैव सिद्धांत में भी शरणागति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ही हम उपासना के सबसे निकट होते हैं। यह बात वरिष्ठ नृत्यांगना डॉ. पद्मजा सुरेश ने नृत्य में अद्वैत कार्यशाला में आयोजित शरणागति सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही। डॉ. पद्मजा ने कहा कि नृत्य एक सहज साधना है। साधना हमें आंतरिक रूप से प्रकाशित करती है। नाट्य साधना के द्वारा ही चेतना की उच्चतम अवस्था तक पंहुचा जा सकता है। चर्चा के सत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉ. पद्मजा ने कहा कि नृत्य के माध्यम से स्थूल से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान उन्होंने नाट्य में अभय मुद्रा का उदारहण देते हुए कहा कि अभय अद्वैत का प्रतीक है और कला महामाया का चिन्मय विलास है।

अंत में डॉ. पद्मजा ने रसामृत में कृष्ण को शक्ति बताते हुए नृत्य के सभी रूपों में नृतक तथा नायिका के भावों को विस्तार दिया। उल्लेखनीय है कि आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मप्र पर्यटन निगम और भारत भवन न्यास, संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चल रही तीन दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन नृत्य में अद्वैत विषय पर विभिन्न सत्र हुए। सत्र में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए भरतनाट्यम नृत्यांगना, कोरियोग्राफर डॉ. रेवती रामचंद्रन ने कहा कि इस तरह के आयोजन मन को विस्तारित करते हैं। यह हमारे आंतरिक एवं आध्यात्मिक विकास में उपयोगी है। उन्होंने कहा कि जब तक हम नृत्य करते हैं तो देह भाव से ऊपर उठकर अपनी पहचान को विलोपित कर देते हैं। कलाकार मंच पर सृष्टिकर्ता की भूमिका में होता है, जो अपनी रचनात्मकता से कला का निर्माण करता है। डॉ. रेवती ने कहा कि भारत में कला परम्परा दर्शकों के उत्थान के लिए है और कलाकार की यही प्राथमिकता भी होना चाहिए।जैसी दृष्टि होती है, वैसी सृष्टि दिखाई देती है।

नृत्य भी एक साधना

कार्यशाला के अगले सत्र में चिन्मय मिशन कोयंबटूर की प्रमुख स्वामिनी विमलानंद सरस्वती ने कहा कि कला का सौन्दर्य आनंद में है। कला की विशेषता है कि उसमें सदैव नवीनता विद्यमान होती है। उन्होंने कहा कि भगवान आसन पर बैठे तो कला है और चलें तो नृत्य है। स्वामिनी ने कहा कि नृत्य भी एक साधना है। जिससे मन परिष्कृत होता है। चर्चा सत्र को आगे बढ़ाते हुए स्वामिनी विमलानंद ने वेदांत का उदारहण देते हुए कहा कि आत्मज्ञान के लिए मन की शुद्धता, सूक्ष्मता एवं एकाग्रता आवश्यक है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्ञान मात्र से होती है, इसलिए आवश्यक है कि मन राग, द्वेष से मुक्त हो।

शोधार्थियों, नृत्य अध्येता और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद

वहीं, शाम को हुए ओपन सत्र में पद्मविभूषण डॉ पद्मा सुब्रमण्यम, स्वामिनी विमलानंद सरस्वती, डॉ कुमकुमधर ने शोधार्थियों, नृत्य अध्येता और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद किया। डॉ.पद्मा सुब्रमण्यम ने कहा कि गुरु के प्रति आत्म-समर्पण करने से संसार की हर वस्तु प्राप्त हो सकती हैं। गुरु ईश्वर के समान है।

जब आप सार्थक दिशा में बढ़ते हैं तो गुरु का आशीष स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। गुरु करुणा के सागर के समान होता है, शिष्य को इसी भाव में रहकर स्वयं को समर्पित करना चाहिए।

डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम ने दी नृत्य प्रस्तुति

बहुकला केंद्र के अंतरंग सभागार में बैठे सैकड़ों कला प्रेमी उस समय विलक्षण प्रस्तुति के साक्षी बने जब स्वयं डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम मंच पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति देने पहुंचीं। 81 वर्षीय डॉ सुब्रमण्यम ने शंकराचार्य विरचित भजन गोविन्दम्, भज गोविन्म... की मनोहारी प्रस्तुति दी। लगभग 15 मिनट की इस प्रस्तुति के दौरान पद्मा जी ने आंगिक, वाचिक, कदमताल और भाव भंगिमाओं का एक ऐसा संसार रचा जिसमें दर्शक पूरी तरह सहभागी बने। मन को छू जाने वाली इस प्रस्तुति के अंत में दर्शकों ने लगभग 5 मिनट तक पदमा जी को स्टेंडिंग ओवियेशन दिया।

भक्ति गीतों पर झूम उठे श्रोता

कार्यशाला के दूसरे दिन का समापन संकीर्तन की प्रस्तुति के साथ हुआ।

इसमें प्रसिद्ध गायक हर्षल पुलेकर ने भक्ति गीतों के माध्यम से सभी को भाव विभोर किया। एक के बाद एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले संकीर्तनों को सुन श्रोता भक्ति रस में झूमते नजर आये। पुलेकर ने जय-जय राधा रमण..., कौन कहता है भगवान आते नहीं.... सहित कई भक्ति गीतों को पेश किया। बहुकला केन्द्र भारत भवन में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन बुधवार को सुबह 9 बजे से विभिन्न सत्र शुरू हुए। शाम को ओपन सत्र तथा संकीर्तन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

उज्जैन में 9 से स्काई डाइविंग फेस्टिवल तीन माह तक रहेगा रोमांच

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। उज्जैन में 9 नवंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू हो रहा है। पहली बार यह लगातार 3 महीने चलेगा। 10 हजार फीट की ऊंचाई से लोग छलांग लगा सकेंगे। एमपी में लगातार चौथे साल स्काई डाइविंग फेस्टिवल हो रहा है। पिछले 3 फेस्टिवल भी भोपाल-खजुराहो के अलावा उज्जैन में हो चुके हैं। अब चौथा फेस्टिवल भी वहीं पर होगा। मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्काई डाइविंग फेस्टिवल हो रहा है। यह उज्जैन में अगले साल 9 फरवरी तक चलेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया, स्काई डाइविंग फेस्टिवल के तीन संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस साल उज्जैन में चौथा संस्करण (तीन माह के लिए) आयोजन किया जा रहा है।

इसलिए किया गया उज्जैन का चयन

उज्जैन में दताना एयरस्ट्रिप पर एडवेंचर लवर्स असमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। उज्जैन में पिछले साल करीब साढ़े 5 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे। इसलिए उज्जैन का चयन किया गया है। इसके अलावा यहां एयर स्पेस खाली है। मौसम भी बेहतर रहता है। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा ने बुकिंग कराई है।

इस संस्करण में आयोजक संस्था स्काय हाई इंडिया द्वारा स्पेशल स्काई-डाइविंग एयरक्राफ्ट न्यू क्रेस्ना 182पी खरीदा गया है। जिसकी क्षमता कुल 6 सदस्यों की है। जिसमें एक बार में 2 प्रतिभागी, 2 एक्सपर्ट के साथ स्काई डाइविंग कर सकेंगे। प्रमुख सचिव शुक्ला के मुताबिक, इन तीन माह में 1000 से अधिक प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है।

स्काई डाईविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन (यूएसपीए) द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई-हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय से पंजीकृत है।

संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई डाइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जाएगी।

जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार का मप्र ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। देशभर में 100 ट्रायबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स (टीएमएमसी) खोलने की योजना है। केंद्र सरकार की इस योजना में आदिवासी बहुल इलाकों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार तैयार करने की योजना है। इसमें 19 जिलों को शामिल करने मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सबसे पहले प्रस्ताव मिलेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के मद्देनजर एमपी सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 19 जिलों में एक-एक टीएमएमसी (ट्रायबल मल्टी-पर्पज मार्केटिंग सेंटर) स्थापित करने का प्रस्ताव भेज दिया है।

11377 गांवों की 93 लाख आबादी को फायदा

मंत्री शाह ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास एवं आदिवासियों के चहुंमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11377 आदिवासी बहुल गांवों का विकास किया जाएगा। इन 51 जिलों में 43 आदिवासी समुदायों के 18 लाख 58 हजार परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल 93 लाख 23 हजार आबादी इस अभियान से सीधे तौर पर लाभान्वित होगी।

2000 वर्गमीटर में एक करोड़ की लागत से तैयार होंगे हाट

प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 19 जिलों में एक-एक करोड़ रुपए लागत से लगभग 2000 स्क्वायर मीटर एरिया में ट्रायबल मल्टी-पर्पज मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जिसका बिल्ट-अप लैंड एरिया करीब 367.80 स्क्वायर मीटर होगा। डॉ. कुमार ने बताया कि यह टीएमएमसी राज्य सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसमें जनजातियों की पुरातन कला, संस्कृति के प्रतीक, शिल्पकारी, चित्रकारी, खिलौने, मिट्टी व बांस से निर्मित उत्पाद आदि की बिक्री भी की जा सकेगी। इससे आदिवासी समाज को आजीविका के नए साधन मिलेंगे और इन्हें अतिरिक्त आय होगी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीम बुधवार सुबह 6 बजे उनके अरेरा कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची और छानबीन शुरू की। बीसी जैन का नाम प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम ने सुबह-सुबह अरेरा कॉलोनी में स्थित बीसी जैन की चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बीसीपी जैन एंड कंपनी के कार्यालय और निवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर की गई है। सुबह 6 बजे ईडी के अधिकारियों की टीम उनके घर और अन्य ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल शुरू की।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने बीसी जैन के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की है। हालांकि, फिलहाल ईडी की ओर से इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बीसी जैन की फर्म कई प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायियों के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करती है, जिसके चलते यह छापेमारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीसी जैन मध्यप्रदेश के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक हैं और उनकी फर्म बीसीपी जैन एंड कंपनी बड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। जैन की फर्म द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले मामलों में बड़े वित्तीय लेनदेन और उद्योगों से जुड़ी फाइलें शामिल हैं,

मध्यप्रदेश-राजस्थान के बीच चीता परियोजना के लिए समिति गठित

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच चीता संरक्षण परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने और चीता कॉरिडोर के विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है। यह समिति चीता के संरक्षण, पर्यटन संभावनाओं और क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी। साथ ही, यह हर तीन माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को सौंपेगी। इस समिति के संयुक्त अध्यक्ष मध्यप्रदेश और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य-जीव अभिरक्षक होंगे। अन्य सदस्य के रूप में चीता प्रोजेक्ट के निदेशक, क्षेत्र संचालक/संचालक, वन्य-प्राणी विशेषज्ञ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा नामांकित प्रतिनिधि होंगे। समिति मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच चीता परियोजना कॉरिडोर के लिए एमओयू का मसौदा तैयार करेगी। यह कॉरिडोर चीतों के सुरक्षित भ्रमण और उनके संरक्षण के लिए विकसित किया जाएगा। समिति कूनो और रणथंबौर क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटन के लिए नए मार्गों का मूल्यांकन करेगी। यह पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ चीतों के संरक्षण में भी सहायक होगा। समिति उन अधिकारियों और फ्रंट-लाइन कर्मचारियों के क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देगी, जो कूनो से राजस्थान तक मौजूदा कॉरिडोर में चीतों की निगरानी और गश्त में शामिल हैं।

इससे चीतों की सुरक्षा और संरक्षण में सुधार आएगा। कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्रों से चीतों के भविष्य के माइग्रेशन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का विकास भी समिति के कार्यक्षेत्र में शामिल रहेगा। इसके लिए प्रि-औगमेंटेशन बेस तैयार कर सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

डॉ. शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज, सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक अहम स्तंभ, स्वर-कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह करीब 11 बजे पटना एयरपोर्ट लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर उनके चाहने वाले और प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना स्थित उनके आवास से लोगों के श्रद्धांजलि देने के बाद कल सुबह यानी 07 नवंबर को उनकी अंतिम यात्रा गुलबी घाट के लिए निकाली जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे से अंतिम यात्रा उनके पटना स्थित

आवास से निकाली जाएगी। राजधानी के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि यह वही घाट है जहां कुछ दिनों पहले शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार हुआ था। उधर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत ने एक महान गायिका को खो दिया है। डॉ. शारदा सिन्हा का छठ गीतों में योगदान अतुलनीय है। उनके बिना छठ पर्व की कल्पना अधूरी है। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए छठी मैया से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

शिवराज सिंह चौहान ने भी दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठ महापर्व पर दिवंगत लोकगायिका डॉ. शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉ. शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ महापर्व की कल्पना अधूरी है। छठ पर्व और उनके गीत एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। छठ के दिन ही उनके देवलोक गमन ने इस पर्व को भावुक बना दिया है। उन्होंने डॉ. शारदा सिन्हा के लोकगीतों की महत्ता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी चुनावों, इंडिया गठबंधन, और मध्यप्रदेश उपचुनावों को लेकर कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति डॉ. शारदा सिन्हा के निधन से न केवल उनके प्रशंसक बल्कि कला जगत के सभी कलाकार गहरे शोक में हैं। उनकी आवाज ने न केवल छठ पर्व को बल्कि समस्त भारतीय लोक संगीत को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। उनकी आवाज में बिहार की संस्कृति और परंपरा जीवंत हो उठती थी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। छठ पर्व पर उनकी संगीत रचनाएं हमेशा उनके होने का एहसास कराती रहेंगी। बता दें भोजपुरी गायका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। छठ महापर्व के नहाय खाय वाले दिन शारदा सिन्हा दुनिया छोड़कर चली गई। हर साल छठ पर्व के पहले उनके नए गीत रिलीज किए जाते थे।

सम्पादकीय

पेंसिलवेनिया के बटलर पार्क की तस्वीर ने बदल दी ट्रंप की तकदीर

1× जुलाई की ही बात है 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पेंसिलवेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी। एआर स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए लेकिन उनके कान में चोट लग गई। कुछ सेकेंड के लिए लगा था कि कहानी खत्म। लेकिन वो 'कुछ सेकेंड' ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का टर्निंग प्वाइंट बन गए। ट्रंप अगर अपना सिर दाहिनी तरफ न घुमाते तो इस इलेक्शन में उनका जीतना तो छोड़िए, उनका शायद जीवित रहना भी मुश्किल होता।

1× जुलाई की ही बात है 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पेंसिलवेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी। एआर स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए लेकिन उनके कान में चोट लग गई। कुछ सेकेंड के लिए लगा था कि कहानी खत्म। लेकिन वो 'कुछ सेकेंड' ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का टर्निंग प्वाइंट बन गए। ट्रंप अगर अपना सिर दाहिनी तरफ न घुमाते तो इस इलेक्शन में उनका जीतना तो छोड़िए, उनका शायद जीवित रहना भी मुश्किल होता। जिस तरह से ट्रंप उस गोली से बचे वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने 0.05 सेकेंड के अंतर पर सिर घुमाया। गोली सिर के बजाय दाहिने कान को छेद कर निकल गई। ड़ोनाल्ड ट्रंप ने उस समय खुद भी यह बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिलिसेकेंड्स का अंतर था। अगर आप ध्यान से ट्रंप पर हुए हमले का उस समय का वीडियो देखें तो यह जानकारी पता चलेगी। ट्रंप पोडियम से भाषण देते समय अपने दाहिने तरफ लगी स्क्रीन पर अवैध इमीग्रेशन का आंकड़ा देखते हैं। तभी गोली चली। ट्रंप का सिर दाहिने घूमा। गोली कान छेदते हुए निकल गई। इसके बाद ट्रंप झुक गए। गोली की आवाज आई। गोली कान छेदकर निकली। ट्रंप ने हाथ से दाहिने कान को छूकर देखा। हाथ में खून लगा। तुरंत गोली आने की दिशा में देखते हुए झुक गए। पहली गोली के पांच सेकेंड बाद दूसरा राउंड फायर हुआ। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने स्टेज पर जाकर ट्रंप के चारों तरफ ह्यूमन शील्ड बनाया। तब तक हथियारबंद सैनिकों ने स्टेज पर पोजिशन ली। कुछ ही सेकेंड के बाद छत पर मौजूद स्नाइपर ने हमलावर को गोली मार दी। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के बीच से हाथ उठाकर ट्रंप कहते हैं फाइट, फाइट, फाइट...। इसके बाद ट्रंप को सीधे उनकी कार में ले जाया जाता है। अब अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजेता बनकर उभरे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। पिछले चुनाव में भी वे रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने तब भी हार नहीं मानी और पूरे चार साल का इंतजार किया। जब उनकी पार्टी ने तीसरी बार उन्हें उम्मीदवार बनाया, तब कोई यह नहीं जानता था कि ट्रंप इस चुनाव को जीत जाएंगे। लेकिन, 1× जुलाई 2024 की पेंसिलवेनिया के बटलर पार्क की तस्वीर ने अमेरिकी चुनाव के रुख को ही बदल दिया। इसी जगह पर ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत रही कि ट्रंप जिंदा बच गए और इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की। खून लगे मुंह के साथ मुठ्ठी भींचकर खड़े होने की उनकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था।

इस तस्वीर का असर यह हुआ कि अमेरिका में उनका जनसमर्थन बढ़ गया। शायद दूसरा कोई नेता होता तो वह दोबारा रैली करने से पहले कई बार सोचता। लेकिन, ट्रंप दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने लगभग दो महीने बाद एक बार फिर उसी जगह रैली की, जहां उन पर हमला हुआ था। इस घटना ने भी लोगों के दिलों में ट्रंप के लिए जगह बनाने में काफी मदद की। जब ट्रंप को गोली छूकर निकली थी, तब भी वे मुठ्ठी को हवा में उठाए फाइट-फाइट-फाइट चिल्ला रहे थे। वे इस बात से भी बेखबर थे कि कहीं हमलावर दूसरी बार उनको निशाना न बना दे। हालांकि, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने तुरंत उस हमलावर को ढेर कर दिया था। अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी एफबीआई ने बताया था कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। वह सिर्फ 20 साल का था। वह पेंसिलवेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था, जिसकी ट्रंप के रैली स्थल से दूरी मात्र 70 किमी थी। रैली स्थल पर मौजूद कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने क्रुक्स को कुहनियों के बल रेंगते हुए देखा था और इसकी सूचना पुलिस और सीक्रेट सर्विस को दी थी। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, जांच के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ट्रंप पर हमले के लिए एआर स्टाइल 556 राइफल का इस्तेमाल किया था। यह करीब ×

चुनाव आयोग के 'होमवर्क' पर उठ रहा सवाल

चुनाव आयोग सात दशकों से चुनाव कराता रहा है, लेकिन इस तरह तारीखों में हेरफेर अपवाद स्वरूप ही होता था। अब यह परंपरा-सी बनती जा रही है, अगर ऐसा ही होना है तो चुनाव की महीनों पहले से शुरू होने वाली तैयारियों और होमवर्क का क्या मतलब है? या तो वो अधूरी होती हैं या फिर समग्रता के साथ नहीं होतीं। एक ही साल में यह तीसरी बार है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना की तारीखें चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद बदली हैं। एक बार मतगणना की तो दो बार मतदान की।

एक ही साल में यह तीसरी बार है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना की तारीखें चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद बदली हैं। एक बार मतगणना की तो दो बार मतदान की। चुनाव आयोग के मुताबिक यह राजनीतिक दलों की मांग और जन भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया फैसला है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर भी चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह जताया है।

वोटिंग और काउंटिंग की तारीखें बार-बार बदलने से चुनाव परिणामों पर कितना और कैसा असर होता है, यह बहस का विषय है, लेकिन एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद इस तरह तारीखें बदलने से चुनाव आयोग के होमवर्क पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आयोग तारीखों की घोषणा के पहले इन सब बातों पर समग्रता से विचार नहीं करता या रा'यों के निर्वाचन पदाधिकारी उन्हें क्षेत्र की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की सही जानकारी नहीं देते?

सबसे हैरानी भरा फैसला तो इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख निर्धारित तिथि से पहले खिसकाने का था, क्योंकि आयोग द्वारा घोषित काउंटिंग की तारीख से पहले ही दोनों रा'यों के विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इन विधानसभाओं के चुनाव भी पांच साल पहले चुनाव आयोग ने ही कराए थे।

चुनाव तारीखें बदलने की श्रृंखला में ताजा कड़ी इस माह होने वाले 14 विधानसभाओं के उपचुनावों की तारीखें बदलने की है। पहले चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए मतदान की तारीख 1× नवंबर तय की थी। उस हिसाब से चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया है।

इस बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि 1× नवंबर, 2024 को उपचुनाव वाले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और रा'य स्तरीय राजनीतिक दलों (भाजपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद सहित) और कुछ सामाजिक संगठनों से उसे ज्ञापन मिले हैं। मतदान के दिन बड़े पैमाने पर होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है। ऐसे में मतदान में मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है।

यह भी संयोग ही है कि आयोग की इस घोषणा से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अगले ही मतदान की तारीखें बदलने की खबर आई।

गौरतलब कि देश में दो रा'यों महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ देश में 14 रा'यों की 47 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन चुनाव तारीखों में बदलाव सिर्फ यूपी, पंजाब और केरल की विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए किया गया है। अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा।

उपचुनाव मतदान की तारीखें बढ़ाने के पीछे वजह उत्तरप्रदेश में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार, पंजाब में इसी दिन गुरू नानक देवजी का प्रकाश पर्व और 1× नवंबर से अखंड पाठ शुरू होना तथा केरल में 1× से 15 नवंबर तक कलपथि रास्तोसेल्वम पर्व मनाया जाना है। कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में पवित्र स्नान तो लगभग सभी रा'यों में होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल यूपी पर ध्यान दिया, यह भी अहम बात है।

जहां तक इन त्योहारों की बात है तो इनमें से कोई भी ऐसा पर्व नहीं है, जिसकी तिथि पहले से तय नहीं हो। तो क्या चुनाव आयोग सभी धर्मों के धार्मिक सांस्कृतिक कैलेंडर नहीं देखता या फिर पर्वों की महत्ता का आकलन अपने हिसाब से करता है? आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता है। उसमें यह मुद्दा क्या नहीं उठाया जाता? सियासी पार्टियों की नींद भी देर से क्यों खुलती है? इसके पीछे वोटरों के कम मतदान का भय छिपा होता है या अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव की तारीखें तय करने की चाल होती है?

यह भी विडंबना है कि जहां मतदान को मतदाता का प्राथमिक कर्तव्य बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ समूची व्यवस्था को इस बात से डर भी लगता है कि ऐन वक्त पर वोटर कहीं अपनी धार्मिक निष्ठा को वोटिंग से 'यादा तव'जो न दे दे, हालांकि यह तर्क बहुत वजनदार नहीं है कि केवल किसी धार्मिक पर्व के होने से मतदाता वोट देने नहीं जाते अथवा कम जाते हैं। जब कोई धार्मिक पर्व नहीं होता तब भी कई बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है, मतदाता उदासीन रहता है। इसके पीछे क्या तर्क देंगे?

सवाल जटिल है, लेकिन हमें इसके उत्तर के पीछे के दलीलों को भी समझना होगा। धार्मिक सामाजिक पर्वों की वजह से चुनाव तारीखें बदलने के पीछे के कारण को मान भी लें तो भी किस विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है और किस तिथि तक उस विस चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए, यह काम तो चुनाव आयोग और उसकी मशीनरी का ही है। चुनाव इस देश में 70 सालों से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अपवादस्वरूप ही हुआ होगा कि एक बार आयोग मतगणना की तिथि घोषित कर दे तथा उसे बाद में ख्याल आए कि काउंटिंग विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी।

विस का कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव प्रक्रिया पूरा कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन पांच माह पहले हुए अरूणाचल और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग को यह देर से ध्यान में आया कि मतगणना की जो तारीख उसने तय की है, उसके पहले ही विस कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह विस चुनाव भी आयोग ने ही कराए थे, तो क्या पुराना रिकॉर्ड भी नहीं देखा जाता?

इसके पहले हरियाणा विस चुनाव में भी आयोग ने मतदान की तारीख बदली थी। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वहां सत्तारूढ़ भाजपा हार रही है, इसलिए तारीख बदलवाई गई। हालांकि नतीजा उलटा ही आया। हरियाणा में विस चुनाव के लिए मतदान एक अक्टूबर को होना थे, बाद में इसे बदलकर 4 अक्टूबर किया गया। कारण यह बताया गया कि 1 अक्टूबर को विश्नोई समाज का वार्षिक मेला लगता है। इसी के चलते विश्नोई महासभा ने भी तारीख बदलने की मांग की थी।

सवाल यह है कि चुनाव आयोग मतदान की तारीखें बदलने के मापदंड अलग-अलग क्यों हैं? इस तरह तारीखें बदलना चुनाव आयोग की संवेदनशीलता है या फिर अधूरी तैयारी? गौर करें कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रमजान महीना भी पड़ रहा था तब कई राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने आयोग के सामने चुनाव तारीखें बदलने का आग्रह किया था। उस समय आयोग ने कहा था कि रमजान के लिए चुनाव प्रक्रिया नहीं रोक सकते।

हालांकि इसमें एक पेंच यह भी है कि रमजान पूरे एक माह चलता है। दो तीन दिन के लिए तारीखें बदली जा सकती हैं। लेकिन एक महीना चुनाव कार्यक्रम खिसकाना आसान और व्यावहारिक भी नहीं है। इसी प्रकाण कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में 12 नवंबर से 15 नवंबर तक पुष्कर में लोग पवित्र स्नान करते हैं। मेला भी लगता है। लेकिन राजस्थान की 7 विस सीटों पर उपचुनाव 1× नवंबर को ही हो रहे हैं।

मतदाता की अपनी सोच, समझ और प्राथमिकता होती है। इसमें धार्मिक पर्व और राजनीतिक गुणा भाग कितना आड़े आते हैं, यह शोध का विषय है। लेकिन जो फर्क है, वो यह है कि चुनाव आयोग सात दशकों से चुनाव कराता रहा है, लेकिन इस तरह तारीखों में हेरफेर अपवाद स्वरूप ही होता था। अब यह परंपरा-सी बनती जा रही है, अगर ऐसा ही होना है तो चुनाव की महीनों पहले से शुरू होने वाली तैयारियों और होमवर्क का क्या मतलब है? या तो वो अधूरी होती हैं या फिर समग्रता के साथ नहीं होतीं।

ट्रंप की प्रचंड जीत से दुनिया की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा?

अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत कर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले कोई अमेरिकी नेता नहीं कर सका था। ट्रंप चार साल व्हाइट हाउस से बाहर रहे। तमाम मुकदमे झेले, कोर्टों के चक्कर लगाए, चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर गोली झेली। हम आपको याद दिला दें कि चुनाव प्रचार की शुरूआत में जानलेवा हमले में ट्रंप बाल-बाल बचे थे। उस समय गोली उनके कान को छूकर निकल गयी थी लेकिन अमेरिका को महान बनाने का संकल्प लेकर ट्रंप ने लोगों का समर्थन मांगा और उन्हें भरपूर समर्थन मिल भी गया। ट्रंप पिछला चुनाव करीबी मुकाबले में हार गये थे लेकिन इस बार उन्होंने अच्छे अंतर से चुनाव जीत कर साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास उनके साथ है। ट्रंप के रहते आतंकवादी और उनके आका अपने बिल से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते थे लेकिन पिछले चार सालों में दुनिया में आतंक बढ़ा और अमेरिका के समक्ष भी तमाम नई चुनौतियां खड़ी हुईं। उम्मीद है कि अब ट्रंप के कड़े रुख के चलते आतंकियों, उनके मददगारों और अमेरिकी जनता से पैसे ऐंठ रहे देशों की मौज-मस्ती खत्म होने होगी। इस चुनाव की खास बात यह भी रही कि अमेरिका में भी चुनाव सर्वेक्षण विफल साबित हुए हैं। पहले सबने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है और इस बार का चुनाव अमेरिकी इतिहास में सबसे करीबी मुकाबले के रूप में देखा जायेगा। लेकिन ट्रंप की निर्णायक जीत ने सारे चुनाव पूर्व अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। इसके अलावा, कमला हैरिस को जिस तगड़े चुनाव प्रचार के बावजूद करारी हार झेलनी पड़ी उससे यह अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है कि यदि ट्रंप के मुकाबले जो बाइडन मैदान में उतरे होते तो उन्हें कितनी तगड़ी हार झेलनी पड़ती। दुनिया के लिए क्या होंगे ट्रंप की जीत के मायने, अगर इस पर बात करें तो आपको बता दें कि अब मध्य-पूर्व में जारी जंग और यूक्रेन-रूस युद्ध खत्म होने के आसार बढ़ सकते हैं क्योंकि ट्रंप ने जीत के बाद भी कहा है कि वह युद्ध नहीं चाहते। इसके अलावा, विदेश से सभी सामानों के आयात पर 20 प्रतिशत सार्वभौमिक शुल्क लगाने की ट्रंप की योजना है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान चेतावनी दी थी कि चीन पर 60 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह इससे ज्यादा भी हो सकता है। इन कदमों से मुद्रास्फीति बढ़ने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ ही ऐसे कदमों से प्रतिशोध, व्यापार युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था तहस-नहस होने का भी अंदेशा है।

इसके अलावा, अब यह भी देखना होगा कि मित्र देशों को शत्रु देशों से बचाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता का क्या होता है। हम आपको बता दें कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य होने के नाते इसके अन्य सदस्यों की मदद के लिए आगे आना अमेरिका का दायित्व है। नाटो के अनुच्छेद पांच के अनुसार यदि कोई देश किसी नाटो सदस्य पर हमला करता है तो वह सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसी ही संधियां कर रखी हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके विपरीत ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक देंगे और कीव पर दबाव बनाएंगे कि वह रूस की शर्तों के अनुसार शांति प्रक्रिया अपनाए। ट्रंप बड़े-बड़े संगठनों को ताकत व प्रभाव दिखाने के मंच के रूप में देखने की बजाय खतरे की वजह और बोझ मानते हैं। हम आपको याद दिला दें कि अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इस तरह की रिपोर्टें हाल में देखने को मिली हैं कि अमेरिका के कई पूर्व अधिकारियों को संदेह है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को नाटो से निकालने की कोशिश करेंगे या समर्थन कम करके नाटो की प्रभावशीलता को कमतर कर देंगे। वहीं एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ट्रंप ने हाल में कहा था कि ताइवान को अमेरिका की ओर से मिल रही सुरक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए। ट्रंप की इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि ताइवान की रक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता कमजोर हो सकती है।

इसके अलावा, इस तरह की रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि अमेरिका में आंतरिक व्यवस्था में भी अब बदलाव देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में दक्षिणपंथ की ओर झुकाव रखने वाले एक थिंकटैंक ने 'प्रोजेक्ट 2025' तैयार किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यह प्रोजेक्ट लागू करते हैं तो नौकरशाही में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने पर संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले 50 हजार अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह ट्रंप के प्रति वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन न्याय, ऊर्जा और शिक्षा विभाग के साथ-साथ एफबीआई और फेडरल रिजर्व जैसी असंख्य संघीय एजेंसियों को भंग कर सकता है और अपने नीतिगत एजेंडे को लागू करने के लिए कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक भारत के साथ अमेरिका के संबंधों की बात है तो इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना बेमानी होगा। ट्रंप के साथ व्यापार और आव्रजन को लेकर बातचीत में कठिनाइयां सामने आ सकती हैं हालांकि कई अन्य मुद्दों पर उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा, ट्रंप जानते हैं कि भारत अगले 20-30 वर्षों में किसी समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इसलिए वह इसकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। ट्रंप की जीत के तत्काल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूं। प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश के साथ ट्रंप और अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं।

भारतीय राष्ट्रपति से कितना पावरफुल अमेरिकी प्रेसीडेंट?

रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता में दमदार वापसी की है। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को रेस से बाहर कर दिया। नए चुने गए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को 4 साल के लिए अपने पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में जानते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर क्या-क्या मिल सकता है? उन्हें क्या उड़ता व्हाइट हाउस भी मिलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति को देश-विदेश के दौरों के लिए एक मरीन हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स वन प्लेन भी मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन में अपने आधिकारिक आवास से एयरपोर्ट तक मरीन वन हेलीकॉप्टर में जाते हैं। इसमें भी उनके साथ मरीन कमांडो और सीक्रेट सर्विस के अफसर होते हैं। एयरफोर्स वन हवाई जहाज में करीब 4 हजार वर्ग फुट जगह होती है। इसे फ्लाइंग कैसल और फ्लाइंग व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बेहद सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रपति के लिए अपने रोजाना के कामकाज को करने के लिए व्हाइट हाउस की तरह ही सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। इसमें राष्ट्रपति के अलावा एक बार में 100 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं।

एयरफोर्स वन के साथ उसके जैसे दिखने वाले 2 और बोइंग 747-200बीएस विमान घेरा बनाकर उड़ते हैं। एक तीसरा जंबो विमान भी साथ चलता है, जिसमें ऑफिस स्टॉफ और सुरक्षा अधिकारी होते हैं। 1953 में पहली बार एयर फोर्स वन का आइडिया आया था। उस वक्त आइजनआवर राष्ट्रपति थे। उस वक्त उनका विमान कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट के रास्ते में आ गया था। एयरफोर्स वन में बेहद तगड़ी सुरक्षा होती है। इसमें डायरेक्टेड इन्फ्रारेड काउंटर मेजर्स सिस्टम लगा होता है, जो किसी भी हाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। इसमें किसी दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम करने का सिस्टम होता है, एयरफोर्स वन की तरफ बढ़ रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। एयरफोर्स वन से ही किसी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु हमले की शुरूआत करने की अनुमति है। इसके लिए उसे कांग्रेस की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। प्लेन में कई तरह के जैमर्स लगे होते हैं। एयरफोर्स वन में 386 किमी लंबी वायरिंग शील्ड होती है। यह एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच जैसा होता है, जो किसी भी परमाणु हमले से बचाने में मददगार होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयूज एयर फोर्स बेस से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें लेते हैं। एयरफोर्स वन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। इसे सिचुएशन रूम भी कहा जाता है। इसमें एक प्लाज्मा टीवी लगा होता है, जिससे राष्ट्रपति टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को संबोधित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यात्रा करने के लिए एक लिमोजिन कार मिलती है। उनके साथ चलने वाले सीक्रेट सर्विस के अफसरों का लिमोजिन कारों का काफिला होता है। किसी देश के दौरे पर राष्ट्रपति के साथ एक डमी राष्ट्रपति भी होता है, जिसे हूबहू राष्ट्रपति जैसा ही तैयार किया जाता है, ताकि दुश्मन कन्फ्यूज रहे। लिमोजिन कारें एआई सिक्योरिटी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक सरकारी सेवक माना जाता है, जो सीधे चुनाव से जीतकर आता है। इसीलिए वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसे में देश के सरकारी खजाने से उसकी सैलरी और खर्चों का भुगतान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन किसी अमेरिकी से 6 गुना से ज्यादा होती है। एक अमेरिकी औसतन सालाना तकरीबन 53 लाख रुपए कमाता है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी करीब 3.35 करोड़ रुपए सालाना होती है। उसे बतौर खर्च करीब 42 रुपए और मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी में 2001 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, तभी वेतन बढ़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास और ऑफिस वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है। उसे यहां सब कुछ फ्री मिलता है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस आने पर पहली बार करीब 85 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे वो मनमुताबिक अपने सरकारी निवास को सजाने और व्यवस्थित करने में खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मनोरंजन, स्टाफ और कुक के लिए सालाना 60 लाख रुपए भी मिलते हैं। उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति को कई और भी सुविधाएं मिलती हैं।

बांधवगढ़ नेशनल पार्क की टीम ने किया हाथी के बच्चे का सफल रेस्क्यू

कटनी के बड़वारा वन क्षेत्र में फैली दहशत समाप्त

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कटनी जिले के बड़वारा वन परिक्षेत्र बिलायतकला में कल सुबह से एक हाथी के देढ़ साल के बच्चा देखे जाने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था जिसका आज बांधवगढ़, कटनी का वन अमला मौके पर पहुंच सफल रात रेस्क्यू कर हाथी के बच्चे को पकड़ा गया और बच्चे को कंट्रोल करने के लिए ट्रेंकुलाइज कर शांत कर बांधवगढ़ ले जाया गया। वन विभाग के डायरेक्टर अमित दुबे ने बताया कि कल बांधवगढ़ नेशनल पार्क से भटक कर एक हाथी का बच्चा कटनी जिले के बड़वारा वन परिक्षेत्र बिलायतकला गुड़ाकला ग्राम के खेते में पहुंच गया था जिसके रेस्क्यू के लिए कल से ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क की वन विभाग की टीम कटनी वन विभाग की टीम के साथ हाथी को पकड़ने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। ओर आज बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 4 हाथियों को बुलवाया गया और हाथियों को देख खुद का खुद हाथी का बच्चा पास आ गया और उसे कंट्रोल करने के लिए ट्रेंकुलाइज कर गाड़ी में चढ़ा नेशनल पार्क ले जाया गया है। साथ ही यह भी बताया की बांधवगढ़ में मरे हाथियों के साथ हाथी का बच्चा रहता था और उनसे से ही बिछड़ गया था और वह कटनी के बांधवगढ़ वन परिक्षेत्र पहुंच गया था।

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी का किया औचक निरीक्षण

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के दिए निर्देश

सुशिल सोनी । सिटी चीफ अनूपपुर, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एक्स-रे कक्ष, रक्त जांच कक्ष, नेत्र परीक्षण कक्षा, मरीज पंजीयन केंद्र, ब्लड कलेक्शन केंद्र सहित अन्य विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.बी. अवधिया नगर परिषद जैतहरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री भूपेंद्र सिंह सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी का अमला उपस्थित था। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने

रक्त जांच पंजी का भी निरीक्षण किया तथा मरीज को रक्त जांच सेंपल का रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो रहे हैं अथवा नहीं, के संबंध में भी दूरभाष से मरीजों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने 1 नवंबर से 5 नवंबर तक रक्त जांच कराने आए मरीजों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिस पर बताया गया की 1 नवंबर से 5 नवंबर तक कुल 30 मरीज का रक्त जांच किया गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को एक्स-रे कक्ष का ताला बंद पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से ताला बंद के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एक्स-रे कक्ष में जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, वह तीन दिवस यहां तथा तीन दिवस पुष्पराजगढ़ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित की लिखित ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी में लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सामुदायिक स्वास्थ्य ने केंद्र जैतहरी में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट का निरीक्षण किया तथा रोगी कल्याण समिति से बायोमेट्रिक मशीन का क्रय कर बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नेत्र सहायक, मेडिकल अधिकारी एवं रेडियोग्राफर की अनुपस्थिति पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए।

स्काई डाइविंग फेस्टिवल 09 नवम्बर से उज्जैन में - राज्य मंत्री

पर तीन माह के लिए मिलेगा रोमांचकारी अनुभव

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की मंशानुरूप मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा डाइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन उज्जैन में 9 नवंबर से किया जा रहा है। उज्जैन में तीन माह के लिये पर्यटकों को 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। यह बात संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताई। राज्य मंत्री ने बताया कि संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई डाइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जायेगी। यह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई-डाइविंग फेस्टिवल के तीन संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में चतुर्थ संस्करण (तीन माह के लिए) आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयरस्ट्रिप पर एडवेंचर लवर्स असमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। बुकिंग की जा सकती है।

एक हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद

इस संस्करण में आयोजक संस्था *Sky-high India* द्वारा स्पेशल स्काई-डाइविंग *Aircraft New CESS-NA 182P Aircraft* द्वारा स्काई डाइविंग हेतु प्रयोग किया जायेगा, जिसकी क्षमता कुल 06 सदस्यों की है, जिसमें एक बार में 02 प्रतिभागी, 02 *Instructors* के साथ स्काई डाइविंग कर सकेंगे। तीन माह में 1000 से अधिक प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है। भविष्य में स्काई-डाइविंग के साथ अन्य एयरबेस्ड गतिविधि भी संचालित की जावेंगी।

आधुनिक और बेहद सुरक्षित होगी राईड स्काई डाईविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डी.जी.सी.ऐ) एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन (यू.एस.पी.ए.) स्क्र द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई-हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय से पंजीकृत है।

सी.आर.सी. छतरपुर ने दिव्यागता विषय पर की जन जागरूकता कार्यशाला

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.) - छतरपुर (अ. या. जं. रा. वा. श्र. दि. सं.) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के तत्वावधान मे जिला जन शिक्षा केंद्र कार्यालय के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजित किया जिसमे मुख्य अतिथि मुकेश कुमार द्विवेदी डीपीसी दमोह , विशिष्ठ अतिथि अभय दुबे, पूर्व नेशनल ट्रस्ट सदस्य ,अध्यक्ष निशक्त व्यक्ति अभिभावक संघ जबलपुर , मुकेश कुमार पटेल,पुनर्वास अधिकारी सीआरसी छतरपुर,संगीता मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी डीडीआरसी दमोह , नितिन कुमार पटेल सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन विभाग दमोह, हेमंत रजक एनजीओ सदस्य,राम सेन एपीसीआईडीईडी शिक्षा विभाग दमोह,ने सरस्वती माता के चित्र माल्या अर्पित कर कार्यक्रम की शुरूआत की इसके बाद अतिथियों का मुकेश कुमार पटेल पुनर्वास अधिकारी, प्रदीप सोनी, आशु बपसे,डीडीआरसी, नरेन्द्र प्रताप सिंह (विशेष शिक्षक) ने स्वागत किया तथा दिव्यागता के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं के सदस्य हेमेंद्र रजक, जागेश सिंह लोधी, नितिन कुमार,रुकसार का सॉल व श्रीफल से सम्मानित किया, इसके बाद अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया और कार्यक्रम

की प्रसनशा की तथा मुकेश कुमार द्विवेदी जिला परियोजना समन्वयक (सर्व शिक्षा अभियान) ने शिक्षा विभाग से चल रही दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, विश्व पी.× ओ. दिवस के अवसर पर चंद्रेश राठौर पी×ओ डीडीआरसी दमोह, ने विस्तार जानकारी दी इसके बाद अभय दुबे ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जो एनजीओ के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं उसकी जानकारी दी तथा नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से सीपी, एएसडी,एमडी, आईडीडी के दिव्यांगजनों को निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम एक लाख रुपए का लाभ दिया जाता उसकी और लीगल गार्जियन शिप की विस्तृत जानकारी दी और राम सेन ने शिक्षा विभाग से जो संसाधन केंद्र, दिव्यांग बच्चों को छात्र वृत्ति योजना की जानकारी दी, नितिन पटेल सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग दमोह ने मध्य प्रदेश सरकार की दिव्यांग जनों को चल रही योजनाओं की जानकारी दी अंत में मुकेश कुमार पटेल ने सीआरसी छतरपुर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से द्वारा चल रही विभिन्न योजना एडीप योजना, यूडीआईडीडी योजना , स्पेशल डिप्लोम, दिव्यांग नेशनल फंड तथा दिव्यांग अधिकारी अधिनियम 2016 क़ानून और संस्थाओं को शसक्त करने की प्रकिया की विस्तृत जानकारी दी, कार्यशाला में जन शिक्षा केंद्र के अधिकारी और शिक्षक, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन शसक्तिकरण विभाग दमोह ने कार्यक्रम में सहयोग किया तथा निशक्तजन व्यक्ति अभिभावक संघ जबलपुर, प्रेरणा विशेष शिक्षा संस्थान एवं पुनर्वास केंद दमोह, अंध मूकबधिर स्कूल दमोह, दिव्यांगजन शसक्तिकरण संस्थान दमोह, कर्म निष्ठा विकलांग उत्थान समिति दमोह, सीएबीएमपी, आदि संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे कार्यक्रम विस्तृत जानकारी प्रदान की इसके बाद पर ने में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों रेखा सिंह प्रभारी जनपद शिक्षा केंद पथरिया, प्रभा सिंह राय एम आर सी बतियागढ़, गीता गुप्ता, रूप नारायण,एमआरसी दमोह, मस्तराम एमआरसी तेंदूखेड़ा, सूची कुमारी हटा एमआरसी, नरेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य प्रेरणा सेंटर, साहिल, मिथलेश, सुषमा, संजय, आदि उपस्थित रहे सभी का आभार कार्यक्रम के समन्वयक मुकेश कुमार पटेल ने व्यक्त किया और सफल आयोजन की डॉ.राजमणि पाल निदेशक सीआरसी छतरपुर ने शुभकामनाएं दी।

ग्राम पंचायत बैठक में पहली बार पारित अजीबो गरीब प्रस्ताव पास

पंच एवं सरपंचों को दी जाए ग्राम विकास के कार्यों के लिए आने वाली राशि में से 10% कमीशन की राशि

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सालरगोंदी में ग्राम पंचायत बैठक में पारित किया गया ये मामला ऐसा है जो आज के पहले कभी नहीं हुआ उप सरपंच सोनिया बाई द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक कार्यों में से 5त्न की राशि पंचों को मिलनी चाहिए अगर ये राशि नहीं दी जाती है तो कोई भी कार्य सही रूप से नहीं चलने देंगे सरपंच विक्रम प्रसाद द्वारा शासकीय किसी भी कार्य में कोई सहयोग नहीं किया जायेगा सरपंच प्रत्येक कार्य में पहले ही 10त्नकी राशि की मांग करता है , ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 12/8/2024 को सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा की गई उपस्थित पंचों के समक्ष सोनिया बाई नाराबदिया बाई, ज्ञानवती बाई, पतिलाल बैसाखू सरिता बाई, ओमप्रकाश, एवं अन्य सदस्यों की सहमति से ये बेतुका प्रस्ताव पास किया गया है इसमें सचिव की मनाही होने एवं इसको गलत ठहराने के कारण सचिव की जनसुनवाई में जिला पंचायत सी ई ओ के पास सचिव की गलत शिकायत पंचों द्वारा की गई इस विषय में सचिव ने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा जिसमें ये सारी जानकारी सामने आई है ।जन सुनवाई में हुई शिकायत के आधार पर सचिव जयंती पनडिया ने मीडिया के समक्ष रखा अपना पक्ष कहा हुई झूठी शिकायत।

अनुपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत

ग्राम पंचायत सागरगोंदी पंचायत के कुछ पंच आज जिला पंचायत सीईओ साहब के पास जनसुनवाई में शिकायत की कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत का विकास नहीं किया जा रहा है जिसका खंडन करते ग्राम पंचायत की सचिव जयंती पनाडिया ने मीडिया के पास आकर बयान दिया कि ये शिकायत निराधार है

उनकी ग्राम पंचायत में पदस्थापना के बाद कोई भी शौचालय निर्माण स्वीकृत न होने का कारण मूलत: ये है कि पिछले सचिव एवं सरपंच द्वारा जीतने ग्रामीडों को शौचालय निर्माण का लाभ मिलना था वह मिल चुका था जिस कारण नए शौचालय नियमानुसार स्वीकृत नहीं किए जा सकते एवं सामुदायिक शौचालय के लिए प्रस्ताव जनपद में दे दिया गया है स्वीकृत होते ही कार्य कराया जाएगा सी सी रोड का भी प्रस्ताव जनपद में दिया गया है उसको भी स्वीकृत होने पर बनाया जाएगा ।। शिकायत में दूसरी ग्राम पंचायत में पदस्त सचिव सुरेंद्र मिश्रा जी के दखल पर जयंती जी ने बताया कि सीनियर सचिव होने एवं पूर्व में इसी पंचायत के सचिव होने के कारण उनसे सलाह ले लेती हु कि कार्य कैसे पूर्ण नियमानुसार किया जाए, मेरे नियमानुसार कार्य किए जाने के कारणसरपंच एव अन्य पंचों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाता जिस कारण यह मेरी शिकायत मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से करते है एवं मुझे अनायास ही प्रताड़ित करते है।

योगी सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल तत्काल घोषित करें :- भगत सिंह वर्मा

गन्ना किसानों को बकाया भुगतान व ब्याज तुरंत दिलाए सरकार :- भगत सिंह वर्मा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद (सहारनपुर)। ग्राम गंगदासपुर जट में एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि डेढ़ माह से गन्ना सीजन शुरू हो चुका है। और प्रदेश की अधिकांश चीनी मिल चल चुकी हैं। इसके बावजूद भी अभी तक भाजपा की योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। अभी भी पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान व पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज चीनी मिलों पर बकाया है। पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 73 करोड रुपए त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद पर बकाया है। पड़ोसी चीनी मिल गांगनौली पर पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान व ब्याज अभी तक बकाया है। जिस पर प्रदेश की योगी सरकार मौन बनी हुई है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार गन्ना उत्पादन पर बढ़ती हुई लागत को देखते हुए गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल तत्काल घोषित करें। इस वर्ष गन्ने की उत्पादन लागत 550 रुपए कुंतल है। डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% के तहत गन्ने का लाभकारी मूल्य 825 कुंतल होना चाहिए। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि जिन चीनी मिलों पर पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान व ब्याज बकाया है उन्हें गन्ना किसानों से दुलाई किराया काटने का अधिकार नहीं है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि कृषि यंत्र खाद बीज कीटनाशक डीजल से जीएसटी हटाकर किसानों की फसलों की लागत कम कराई जाए। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर सरकार लागत मूल्य भी नहीं दिला रही है जिसके कारण किसानों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में परेशानी हो रही है और उनकी फीस भी फसलों से नहीं निकल रही है और किस के बुजुर्ग माता-पिता को दवाई की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अन्नदाता किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। भगत सिंह वर्मा ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल घोषित नहीं किया और चीनी मिलों से पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान व ब्याज नहीं दिलाया तो गन्ना किसान सड़कों पर आकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार हाफिज मुर्तजा त्यागी ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर ही गन्ना किसानों की समस्याएं हल होगी। पृथक राज्य के लिए किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार, बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार, युवा और छात्र आगे आकर संघर्ष में भागीदारी करें। बैठक का संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार किसान विरोधी है और गन्ना किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मांगेराम यादव, जिला मंत्री महबूब हसन, हाजी बुद्धू हसन, मोहम्मद बारीक त्यागी, मोहम्मद तसलीम, रविंद्र चौधरी, आकाश चौधरी, अमन सिंह गिल, पदम सिंह, अमित कुमार, सुमित वर्मा, संत सिंह, समरपाल सिंह, सुरेंद्र प्रधान ने भाग लिया।

सहारनपुर की चीनी मिलों पर 92.70 करोड़ बकाया

अकेले गागनौली चीनी मिल पर ही 63.34 करोड़ बकाया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर। नया गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है लेकिन जिले की तीन चीनी मिलें गागनौली, गागलहेड़ी और टोडरपुर पर करीब 92.70 करोड़ रूपए किसानों का बकाया है। जिला गन्नाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि अकेले गागनौली चीनी मिल पर ही 63.34 करोड़ बकाया है। गागलहेड़ी चीनी मिल पर 16.59 करोड़ रूपए और टोडरपुर चीनी मिल पर 12.77 करोड़ रूपए बकाया है। तीनों चीनी मिलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द इस बकाया राशि का भुगतान करें। इन तीनों चीनी मिल क्षेत्र के किसानों में बकाया भुगतान को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कई किसानों ने यहां तक कह दिया है कि भुगतान ना होने की हालत में वे इन मिलों को गन्ना आपूर्ति नहीं करेंगे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने गन्ना अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए कि वे शीघ्र से शीघ्र बकाया गन्ना राशि का भुगतान कराएं। जिले की ज्यादातर चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। जिले की सबसे बड़ी देवबंद की त्रिवेणी चीनी मिल शुरू हो गई है। मिल के उपाध्यक्ष पुष्कर मिश्र ने नए पेराई सत्र का विधिवत उद्घाटन किया। गन्ना उपायुक्त ओमप्रकाश सिंह का कहना है कि 10 नवंबर तक जिले की सभी चीनी मिलें पेराई शुरू कर देंगी।

रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के सम्पूर्ण उपाय किए जाएं :- जिलाधिकारी मनीष बंसल

कोई भी व्यक्ति खुले में न सोने पाए :- मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आगामी सर्दी के दृष्टिगत कम्बल वितरण, अलाव जलाये जाने एवं शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समाज के संभ्रांत व्यक्तियों, उद्यमियों, व्यापार बंधुओं, अधिकारियों एवं गन्ना मिल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी संभ्रांत व्यक्तियों से अपील करते हुए कहा कि गरीब, असहाय और निराश्रितों को ठंड से बचाव के कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी और शीतलहर के दृष्टिगत रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के साथ ही साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाये जाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोने पाये। उसकी रात रैन बसेरे में ही गुजरनी चाहिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नगर निगम को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 200 व्यक्तियों की क्षमता वाले रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ नगर पालिकाओं में आवश्यकतानुसार रैन बसेरे बनाने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत को मेडिकल कॉलेज के पास 50 लोगों की क्षमता वाला रैन बसेरा बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेन बसेरा में अलाव के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग एवं निराश्रितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, एस0पी0 ग्रामीण सागर जैन, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, एआरटीओ प्रशासन एमपी सिंह, आलोक कुमार अग्रवाल, अनूप खन्ना, अनुपम गुप्ता सहित समाज के संभ्रांत नागरिक एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मो. बड़ोदिया में होगा वाटरशेड यात्रा अभियान का आयोजन

ग्रामीणों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक प्रयास

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, जिले की जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया में विभिन्न तिथियों में वाटरशेड यात्रा अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक ग्रामीणों तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 परियोजना की उपयोगिता हेतु किए गए कार्यों, इनके परिणामों और इनसे ग्रामीणों को प्राप्त हुए लाभों के सदर्भ में जागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ाना है। कलेक्टर एवं मिशन लीडर ऋजु बाफना ने बताया कि वाटरशेड यात्रा अभियान के मुख्यतः दो घटक होंगे। प्रथम घटक के अंतर्गत परियोजना के सभी ग्रामों में विभिन्न प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और द्वितीय घटक में 11 एवं 12 नवम्बर 2024 को योजना के विभिन्न आयामों को समाहित कर डिजाईन की गई प्रचार वैन का भ्रमण और विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को आयोजित कर संपूर्ण अभियान का समापन किया जाएगा। वाटरशेड यात्रा अभियान के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख समन्वयक होंगे तथा परियोजना स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय घटक के विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रोजेक्ट लीडर जनपद पंचायत मोमन बड़ोदिया इस अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। जिला परियोजना अधिकारी वाटरशेड तथा परियोजना के सभी डब्ल्यू डीटी सदस्य संपूर्ण अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों के आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे। वाटरशेड यात्रा अभियान अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों में अन्य विभागों, जनअभियान परिषद, मप्र राज्य आजिविका मिशन, स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला एवं विकासखण्ड स्तर के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका के साथ स्वयं अथवा अधिनस्थों के साथ सम्मिलित होंगे। इस अभियान के तहत नुक्कड़, नाटक, चित्रकलां प्रतियोगिता, निबंध, प्रतियोगिता, सचित्र दीवार लेखन, पानी की रैली एवं पाठशाला, अतिथियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदर्शनी कार्यों का लोकार्पण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कारों का वितरण आदि गतिविधियों का अयोजन किया जाएगा। परियोजना क्रमांक 1 में जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया के ग्राम बुरलाय, धतरावदा में 07 नवम्बर, गोविंदा एवं बड़बेली में 08 नवम्बर, बरनावद, बाड़ोदी में 09 नवम्बर, जावदी, सागडिया में 10 नवम्बर तथा सिमरोल में 11 नवम्बर को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। इसी प्रकार परियोजना क्रमांक 2 में जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया के ग्राम अनखली, नागझिरी, पिथाखेड़ी कलमोदिया एवं देवरीमुल्ला में 07 नवम्बर, मताना, खरहरखेड़ी, बड़ोनी में 08 नवम्बर, भण्डेडी, बीरागांव में 09 नवम्बर, सारसी, ढाकनी में 10 नवम्बर तथा मटेवा में 12 नवम्बर को गतिविधियों का आयोजन होगा।

गांधीसागर समूह जलप्रदाय योजना बनेगी 920 ग्रामों के लिये वरदानः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मंदसौर जिले के लगभग ढाई लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसम्बर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना से न सिर्फ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीणों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने बताया कि पहले जहां हर साल गर्मी में पानी की गंभीर कमी होती थी और लोग जलस्त्रोतों के सूखने के कारण पानी की समस्या से जूझते थे, वहीं अब गांधीसागर बांध से जल आपूर्ति का एक स्थिर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस योजना से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा रहा है। गांधीसागर जलप्रदाय योजना का उद्देश्य न सिर्फ पानी की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है और योजना के पूरा होने पर भी अन्य कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के समुचित संचालन के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये समितियां जल आपूर्ति और इसके प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी, जिससे जल संकट का स्थायी समाधान और ग्रामीणों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह योजना न सिर्फ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि जल जनित रोगों में कमी लाने और ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ बनाने का भी काम करेगी। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने से निजात मिलेगी और वह अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। गांधीसागर जलप्रदाय योजना मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद और स्थायी समाधान लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ जल संकट का समाधान होगा, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के स्तर में भी सुधार होगा। जल आपूर्ति के इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ, मंदसौर जिले में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।

छठ पर्व का भारतीय संस्कृति में है विशेष महत्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री उज्जैन में छठ पर्व कार्यक्रम में 08 नवंबर को सुबह वर्चुअली होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का बुधवार रात्री को उज्जैन मिथिलांचल विकास समिति द्वारा छठ पर्व पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष छठ पर्व का आयोजन 08 नवंबर को प्रात: 07:30 पर विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस स्थित विक्रम सरोवर में किया जा रहा है। छठ पर्व पर होनेवाली सूर्य देवता की उपासना एवं पूजा-अर्चना में क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम अलीराजपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक

अलीराजपुर- झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान एवं कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम अलीराजपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया । बैठक में जल निगम महाप्रबंधक कुलदीप ने बताया कि जिले के 539 ग्रामों में नल जल पहुंचाने के लिए 1 हजार 15 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन का संचालन किया जा रहा है। इन 539 ग्रामों में 381 ग्रामों में पाईप लाइन की स्थापना एवं टंकी निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा एवं शेष 158 ग्रामों में पीएचई विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा । सभी ग्रामों में जल स्पलाई जल निगम द्वारा ही किया जाएगा । उन्होंने बताया कि 106 एमएलडी की क्षमता का इंटेक वेल ककराना में , 87.12 एमएलडी की क्षमता का जल शोधन यंत्र कुलवट में स्थापित किया जा रहा है। कार्य में प्रगति लाई जाए ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल घरों में ही उपलब्ध हो सके - सांसद श्रीमती चौहान सांसद श्रीमती चौहान ने निर्माण एजेन्सी द्वारा किये गए कार्यो की समीक्षा की उन्होंने कहा कि सितम्बर 2025 तक जिले के प्रत्येक ग्राम , फलिए एवं घरों में नल जल पहुंचाना शासन का लक्ष्य है । निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त कार्य में आवश्यक गति से कार्य नहीं किया जा रहा है । इस कार्य में प्रगति लाई जाए ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल घरों में ही उपलब्ध हो सके ।

कोई भी हितग्राहि इस योजना के लाभ से वंचित न रहे - कलेक्टर डॉ बेडेकर कलेक्टर डॉ बेडेकर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा टीएल बैठक में की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने निर्देशित किया की सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक कार्यशाला आयोजित कर योजना के अंतर्गत दिए जा रहे नल कनेक्शन एवं पाइप लाइन बिछाने के कार्य का ग्रामवार एवं फलियेवार पुर्ण सत्यापन किया जाए ताकि कोई भी हितग्राहि इस योजना के लाभ से वंचित न रहे । इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर सिंह , अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे ,सहित जल निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 2024-25 में ''वेज एंड मीन्स'' एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित कर भारतीय खाद निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने को मंजूरी देने पर आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसान-कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया जाना अभिनंदनीय- वंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये निर्णय एक ओर कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा, वहीं किसानों के कल्याण के लिए नए युग की नींव रखेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान सम्मान निधि, सस्ते खाद, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और श्रीअन्न जैसे किसान समृद्धि के विभिन्न निर्णयों के क्रम में इस सौगात के लिए प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

फोर्टिफाइड चावल व डबल फोर्टिफाइड नमक के प्रचार-प्रसार के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को फोर्टिफाइड चावल व नमक के प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित 837 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से 369384 परिवारों तथा 1583360 हितग्राहियो को फोर्टिफाइड चावल और डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण किया जा रहा है।फोर्टिफाइड चावल व नमक जनस्वास्थ्य के लिए होने वाले लाभ के बारे में न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल एमपीवीएचए इंदौर से संभागीय समन्वयक नयन पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फोर्टिफाइड चावल के कर्नल और चावल को फोर्टिफाइड चावल मील में तैयार किया जाता है। मिल में तैयार किये गये फोर्टीफाइड चावल को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरित होने वाले चावल में शासन की मार्गदर्शिका के अनुसार एक निश्चित मात्रा में एक प्रतिशत फोर्टीफाइड चावल जाता है। फोर्टीफाईड चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिले होते है, जो कि मानव शरीर को बेहतर पोषण प्रदान करते है इसमे आयरन जो कि खून की कमी जैसी स्थिति या अनिमिया से बचाव करता है, वही फोलिक एसिड गर्भवती महिला मे गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के उचित विकास के लिए आवश्यक होता है और विटामिन बी 12 खून मे लाल रक्त कणिकाओ के निर्माण मे सहायक होता है। साथ ही नमक में भी आयोडीन के साथ आयरन मिलाया गया है, यह फोर्टिफाइड चावल और नमक कैसे मिल में बनता है कैसे इसमे पोषक तत्वो को मिलाया जाता है उक्त बाते भी प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया साथ ही क्षेत्र में इनसे जुड़ी भ्रांतिया को दूर करते हुए वास्तविक तथ्य बताए जैसे नमक में जो कभी कभी काले कण दिखाई देते है वह आयरन के है यह कचरा, मिट्टी या रेत नहीं है, चावल मे भी जो अलग से दिखने वाले दाने है वह पोषकतत्व से भरपूर है प्लास्टिक या अन्य पदार्थ नहीं है यह चावल के आटे और पोषक तत्व के पाउडर से मिला कर बना होता है। डबल फोर्टिफाइड नमक व फोर्टिफाइड चावल शासन की उचित मूल्य दुकानों के साथ-साथ आंगनवाड़ियों और मध्यान्ह भोजन में प्रदान किया जा रहा है। कार्यशाला में जिले स्तरीय अधिकारियों के साथ आनलाईन में जिले के समस्त ब्लाक के समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे।

क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में : मुख्यमंत्री

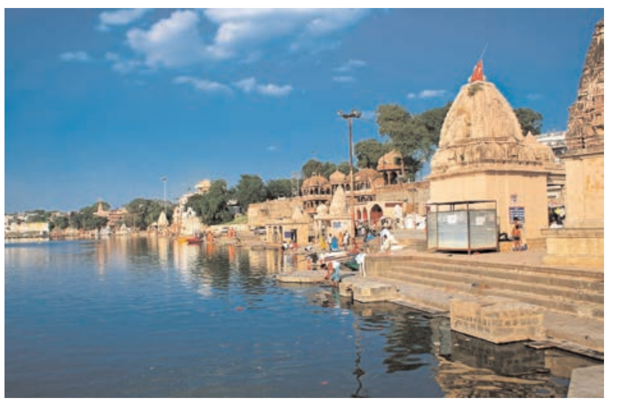

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये विशेष व्यवस्था? करने राज्य सरकार की टीम ने एकजुट होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। सिंहस्थ- 2028 की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांक्षिप्रा के शुद्धीकरण के लिए 599 करोड़ रूपये लागत की कान्ह-क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही उज्जैन में आवागमन के लिये चौतरफा सड़क, ब्रिज बनाकर फोर-लेन मार्ग भी बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ आवागमन और सौन्दर्यीकरण से संबंधित अनेक अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन पहुँचने वाले श्रद्धालु, विशेष रूप से बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिये ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे कम समय में सहजता से क्षिप्रा के घाटों और श्रद्धा स्थलों तक पहुँच सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में साधु-संतों के लिये इस बार विशेष पहल कर हरिद्वार की तरह स्थायी धार्मिक नगरी और आश्रम बनाये जायेंगे। इसके लिये सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत-महंतों के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। इन प्रयासों से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के माध्यम से उज्जैन को विश्व पटल पर प्रमुखधार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में पहचान दिलाने के समग्र प्रयास किये जा रहे है। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मन्दिर की पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिये सदावल में हेलीपेड का निर्माण भी किया जायेगा। साथ ही उज्जैन की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की पहल भी की जा रही है। उज्जैन को जोड़ने वाले चारों ओर के मार्गों को फोरलेन किया जायेगा, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये स्थाई प्रकृति के 62 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें आधुनिक बिजली ग्रिड, नवीन विद्युत लाइन, इंटर कनेक्शन और नवीन उपकेन्द्र बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य से उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन हो चुका है। इनमें प्रमुख रूप से हरिफाटक-लालपुल-मुल्लापुरा फोरलेन मार्ग शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी, 2 नग 2 लेन आरओबी और क्षिप्रा पर 2-लेन ब्रिज सहित फोरलेन मार्ग, उज्जैन बड़नगर बाईपास टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य, बडावदा-कलसी-नागदा से दोत्रु मार्ग का निर्माण, नागदा गिद्धगढ़ विदखेड़ा मोकड़ी मार्ग, तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग, रालामंडल-कांकरिया-चिराखान-लेकोड़ा-झिरोलिया-बारोदा-हमीरखेड़ी-उमरिया मार्ग, लालपुर से चिंतामन गणेश मंदिर, बड़ापुल-रणजीत-हनुमान-मोजमखेड़ी मार्ग, वाकंणकर पुल से दाऊद खेड़ी, करोहन-नाईखेड़ी-पंचक्रोशी मार्ग, खाचरोद-बड़नगर-बायपास, सेदरी से बड़ावदा, मुरानाबाद से बेड़ावन्या, रतलाम खाचरोद का शेष भाग का मजबूतीकरण, सदावल हेलीपैड निर्माण, जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, रूदाहेड़ा से गुनई-महिदपुर से काचरिया एवं महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ, सुतारखेड़ा एप्रोच रोड-मीन रोड से सुतारखेड़ा एवं रूदाहेड़ा एप्रोच रोड और मक्सी-तराना-रूपाखेड़ी एवं कानीपुरा-तराना मार्ग, मास्टर माईंड स्कूल तराना से लिम्बादित मेन रोड का काम प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक विकसित होने के बाद उज्जैन वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिये अभी से कार्य प्रारंभ कर दिये है, जिससे यहाँ आने वाले श्रृद्धालु और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

एमवाय, सीएआर-टी थैरेपी से ब्ल्ड कैंसर का उपचार करने वाला देश का पहला अस्पताल

आधुनिकतम चिकित्सा तकनीक और सेवाओं से प्रदेश बनेगा अग्रणी चिकित्सा हब : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराने के लिए सतत प्रयासरत है। इम्यूनोथेरैपी जैसी उन्नत तकनीक का एमवाय अस्पताल में शुभारंभ इस दिशा में एक मील का पत्थर है। यह पहल उन मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जिनके इलाज में पारंपरिक पद्धतियाँ कारगर नहीं रही हैं। यह कदम चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान को एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिकतम चिकित्सकीय तकनीकों और सेवाओं से युक्त कर मध्यप्रदेश को देश का प्रमुख चिकित्सा हब बनाया जाये। मध्यप्रदेश का एमवायएच (महाराजा यशवंतराव अस्पताल) इन्दौर देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत सीएआर-टी थेरेपी शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सीएआर-टी कोशिकाएं ट्यूमर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से करती हैं समाप्त एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने बताया कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) नामक तकनीक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी लाभ नहीं मिलने वाले मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती है। सीएआर-टी थेरेपी की प्रक्रिया के लिए पहले मरीज का रक्त सैंपल ले लिया गया है। इसके तहत बी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित मरीज की श्वेत रक्त कोशिकाओं को एफरेसिस मशीन द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसके बाद, इन कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाएगा ताकि ये विशेष काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) ला सकें, जो कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। संशोधित सीएआर-टी कोशिकाओं को मरीज में प्रत्यारोपित करने के बाद, ये ट्यूमर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से समाप्त करती हैं। एमवायएच में इस सुविधा की शुरुआत के साथ ही देश में शासकीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला एमवायएच पहला अस्पताल बन गया है। यहां पर इम्यूनोथेरैपी का खर्च लगभग 30 लाख रुपये है, जो कि अमेरिका में इसी तकनीक के लिए लगने वाले लगभग 4 करोड़ रुपये की तुलना में बेहद कम है। इस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया को संयुक्त रूप से आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया है। भारत में यह तकनीक नई है। अभी तक इसके तहत लगभग 150 मरीजों का इलाज हुआ है। इंदौर के इस अस्पताल में 20 नवंबर को इस प्रक्रिया के माध्यम से पहले मरीज का इलाज किया जाएगा। इसके पहले, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए इंदौर में कीमोथेरैपी, रेडिएशन थेरैपी, सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब इम्यूनोथेरैपी के जुड़ जाने से इन मरीजों के लिए उपचार के विकल्प और विस्तृत हो गए हैं। इम्यूनोथेरैपी (सीएआर टी सेल) कैसे करती है कार्य इस तकनीक में मुख्यत: टी कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जिससे ये कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर सकें। सामान्यत: श्वेत रक्त कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं- बी और टी कोशिकाएं। इम्यूनोथेरैपी में टी कोशिकाओं को श्वेत रक्त कोशिकाओं से अलग करके, आनुवंशिक संशोधन किया जाता है। इसके लिए वायरल वैक्टर की मदद ली जाती है ताकि टी-कोशिकाएं अपनी सतह पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (सीएआर) स्थापित कर सकें। इन रिसेप्टर्स की विशेषता होती है कि वे कैंसर कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित विशेष प्रोटीन को पहचान सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। थैरेपी के बाद मरीज को एक से दो सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है ताकि उसकी स्थिति पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके।

वीरेंद्र एकीकृत बागवानी मिशन का लाभ लेकर, साल के कमा रहे 14 लाख रू.

मंदसौर। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही योजना एकीकृत बागवानी मिशन योजना का आज के समय में किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेकर कई किसान लखपति भी हुए हैं। इसी का एक उदाहरण है वीरेंद्र पाटीदार (7489096793)। सीतामऊ तहसील ग्राम गोपालपुर के रहने वाले हैं। वीरेंद्र ने इस योजना का लाभ वर्ष 2020-21 में लिया। इस योजना के माध्यम से वीरेंद्र को 1 लाख 20 हजार का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान की मदद से इन्होंने अपने पांच बिगा खेत में यूएनआर रायपुर प्रजाति के 1800 अमरूद के पौधे लगाए। सभी पेड़ तीन से चार वर्ष के हो चुके हैं और एक पौधे से इनको 30 से 40 किलो अमरूद प्राप्त होता हैं। वीरेंद्र का कहना है कि अभी अमरूद के पौधे छोटे हैं। जब पौधे और बड़े होंगे, तो इनकी उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ेगी। बाजार से इनको एक किलो अमरूद के बदले 50 से 70 रुपए मिलते है। अमरूद की खेती के दाम पर वीरेंद्र साल भर में 14 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके साथ ही 10 से 15 मजदूर को रोजगार भी दे रखा है, जो की बागवानी की खेती में काम करते हैं। इनके अमरूद शुगर फ्री है और इन अमरूद की बाजार में मांग बहुत रहती है। इनके अमरूद की मांग इतनी रहती है कि इनको बाजार में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि व्यापारी स्वयं उनके खेत से आकर ही सारे फल ले जाते हैं। तापमान मापक यंत्र भी किसान ने खेत में लगा रखा है, जिससे यह पता चलता है कि खेत में पानी कब देना है, खेत में नमी कितनी है एवं यंत्र से मौसम की जानकारी भी मिल जाती है।

न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन

मंदसौर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक सेवा से संबंधित विषयों पर निबंध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री सिद्धार्थ तिवारी ने विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को उक्त प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार और विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती विनीता प्रधान भी उपस्थित रहे। सेंट थॉमस विद्यालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तिवारी ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया और विधिक जागरूकता का संदेश दिया। इसके साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल क्रमांक 2 विद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, नूतन माध्यमिक विद्यालय, और शासकीय बालिका विद्यालय बालागंज ,शासकीय एकीकृत कन्या विद्यालय ग्राम ढ़िकोला, शासकीय बालिका उच्चतर बालिका विद्यालय भानपुरा में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रतिभागियों को उनकी सहभागिता हेतु प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती सीमा नागर, श्रीमती सलमा सैयद, श्री संजय नीमा, श्री मुकेश आचार्य द्वारा भी सक्रिय सहयोग प्रदाय किया गया।

ये रहा वो टर्निंग प्वाइंट, जिसने ट्रंप को फिर बना दिया अमेरिका का राष्ट्रपति

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। पहले ऐसा अनुमान था कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला होगा और दोनों के बीच महीन अंतर रहेगा, लेकिन ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस को 224 वोट मिले हैं।। इसी बीच ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों का शुक्रिया किया और कहा कि वो चुनाव के दौरान किए गए हर वादों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि यह जीत ट्रंप के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। आज हम जानते है कि वह कौन सा टर्निंग प्वाइंट था जिसने उनके इस जीत में बढ़त दिला दी।

आपको बता दें कि 13 जुलाई 2024 को पेंसिलवेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने न केवल उनकी जिंदगी को खतरे में डाला, बल्कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी अभियान के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया। गोली उनके कान के पास से होकर निकली, लेकिन ट्रंप ने उस पल में एक ऐसा कदम उठाया, जिसने उनकी जिंदगी और राजनीतिक भविष्य को बचाया।

कुछ सेकेंड्स में बदल गया सबकुछ

पेंसिलवेनिया में 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने AR Style 556 राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई। गोली उनके कान के पास से निकल गई, जिससे उनकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ा, लेकिन उनकी जान बच गई। 0.05 सेकेंड के भीतर ट्रंप ने अपना सिर दाहिनी तरफ घुमा लिया, जिससे गोली सिर को छेड़े बिना कान के पास से निकल गई। अगर ट्रंप ने यह कदम न उठाया होता, तो उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। हमले के बाद ट्रंप ने खुद माना कि उनकी मौत और जीवन के बीच बस कुछ मिलिसेकंड्स का अंतर था। हमले के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब ट्रंप दाहिनी तरफ घूमे, तो गोली उनके कान से निकल जाती है। अगर उन्होंने अपनी दिशा न बदली होती, तो गोली उनके सिर के अगले हिस्से में लगती, जिससे उनकी जान का बचना लगभग असंभव हो जाता। गोली के बाद तुरंत ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। वे ह्यूमन शील्ड बनाकर उन्हें हमलावर से बचाने में जुट गए। इसके कुछ ही पल बाद, स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप को जल्दी से अपनी कार में ले जाया गया और इस दौरान उन्होंने फाइट, फाइट, फाइट का नारा लगाया, जो उनकी जिंदादिली और दृढ़ता को दर्शाता था।

AR Style 556 राइफल का खतरनाक असर

हमले में जिस AR Style 556 राइफल का इस्तेमाल किया गया था, वह सेमी-ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल थी। यह हथियार 3 किलोग्राम वजन का है और इसकी लंबाई लगभग 35 इंच है। इस राइफल की नली की लंबाई 16.10 इंच है, जिससे यह लंबी दूरी तक टारगेट को प्रभावी तरीके से हिट करने में सक्षम है। यह राइफल एक खतरनाक हथियार थी, जिसे वैध तरीके से खरीदा गया था।

साइंस का योगदान- ट्रंप की जान कैसे बची?

ट्रंप की जान का बचना केवल उनके फुर्तीले फैसले पर निर्भर नहीं था, बल्कि इसमें साइंस का भी योगदान था। गोली के ट्रैक को देखते हुए अगर ट्रंप सिर को दाहिनी तरफ न घुमाते, तो गोली सीधे उनके कनपटी पर लगती और उनके सिर से होकर निकल जाती, जिससे उनकी जान का बच पाना असंभव हो जाता। यह साबित करता है कि कभी-कभी कुछ पलों की सूझबूझ ही जीवन और मृत्यु के बीच फर्क पैदा कर सकती है।

एक नई राजनीतिक दिशा

13 जुलाई 2024 को हुए इस हमले ने ट्रंप की जिंदगी को तो बचाया ही, साथ ही उनके चुनावी संघर्ष को भी नया मोड़ दिया।

इस घटना ने साबित कर दिया कि जब व्यक्ति की जिंदगी और राजनीति दोनों दांव पर लगी हों, तो एक पल का फैसला क्या असर डाल सकता है। ट्रंप के लिए यह हमला उनके जीवन को बचाने के अलावा, उनके चुनावी अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यह पल अमेरिकी राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

हैरिस ने अपनी हार की स्वीकार और दिया ये वचन, बाइडेन ने भी ट्रंप को जीत की दी बधाई

इंटरनैशनल डैस्क. राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप से हार स्वीकार करने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थकों से चुनाव परिणामों को स्वीकार करने का आग्रह किया और रिपब्लिकन पार्टी के नेता को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने का वचन दिया। हॉवर्ड विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रहीं हैरिस (60) ने विश्वविद्यालय में एक भावुक संबोधन में कहा कि ''अमेरिका के लिए किए गए वादे की रोशनी हमेशा जलती रहेगी और उन्होंने इस अभियान को बढ़ावा देने वाली ''लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया। अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के प्रयास में उन्होंने कहा, ''आज मेरा दिल भरा हुआ है। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मेरे दिल में अपने देश के लिए प्रेम और दृढ़ संकल्प है।

उन्होंने कहा, ''इस चुनाव का नतीजा वह नहीं है जो हम चाहते थे, न ही वह जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और न ही वह जिसके लिए हमने वोट दिया था। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूं तो मेरी बात सुनिए तो अमेरिका के लिए किए गए मेरे वादे की लौ हमेशा जगमगाती रहेगी। उन्होंने कहा, ''मैं जानती हूं कि लोग इस समय कई तरह की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। मैं समझती हूं। लेकिन हमें इस चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना है।

हैरिस ने कहा कि उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, ''मैंने ट्रंप से कहा कि हम उन्हें और उनकी टीम को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में मदद करेंगे तथा हम सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करेंगे। उन्होंने कहा, ''हमारे देश में हमारी निष्ठा किसी राष्ट्रपति या पार्टी के प्रति नहीं बल्कि अमेरिका के संविधान के प्रति है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बृहस्पतिवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर उन्हें जीत की बधाई दी। राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी फोन पर बात की और उन्हें उनके ऐतिहासिक अभियान के लिए बधाई दी। ट्रंप के साथ बातचीत में बाइडेन ने सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा देश को एकजुट करने के लिए काम करने के महत्व पर बल दिया। व्हाइट हाउस ने कहा, ''उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए संबंधित कर्मी निकट भविष्य में एक विशिष्ट तिथि को लेकर समन्वय करेंगे।

कनाडा में टिकटॉक के कार्यालय बंद करने का आदेश

इंटरनेशनल डेस्क. कनाडा ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देते हुए चीनी टिकटॉक पर बड़ी कार्रवाई की। कनाडा ने देश में टिकटॉक के सभी व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि, कहा गया कि सरकार कनाडाई लोगों की शॉर्ट-वीडियो एप तक पहुंच या उनके कंटेंट बनाने की रुचि की राह में बाधा नहीं बन रही है।

वहीं ओटावा टिकटॉक के कनाडाई उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, जो चीन स्थित बाइटडांस के स्वामित्व के लिए जांच के दायरे में आया है।

इस मौके पर मंत्री फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन ने एक बयान में कहा, सरकार TikTok Technology Canada Inc के जरिए कनाडा में ByteDance Ltd के संचालन से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को दूर करने के लिए, यह कार्रवाई कर रही है।

बता दें कि ओटावा ने पिछले साल कनाडा में अपने व्यवसाय में निवेश और विस्तार करने की TikTok की योजना की समीक्षा शुरू की थी। ByteDance TikTok की चीनी मूल कंपनी है। कनाडाई कानून के तहत सरकार विदेशी निवेशों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों की समीक्षा कर सकती है। कानून सरकार को ऐसे निवेशों का विवरण सार्वजनिक करने से रोकता है।

ऑस्ट्रेलिया सरकार का बड़ा फैसला: 16 साल तक के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

इंटरनेशनल डेस्क. बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत एक आम समस्या बन चुकी है। मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आ रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को दी।

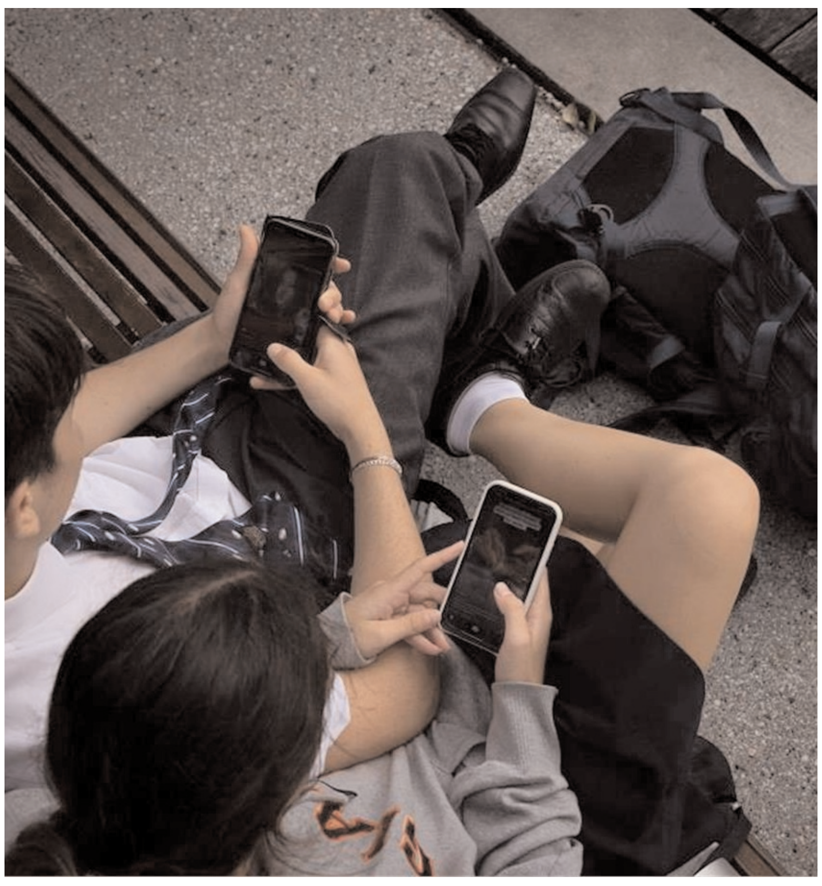

बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि टेक कंपनियां बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने में विफल रही हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम माता-पिता की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के भले के लिए उठाया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर उम्र सीमा लगाने की बात की है। इस साल की शुरुआत में भी उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में चिंता जताई थी।

किस-किस प्लेटफॉर्म पर लागू होगा बैन?

ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड ने बताया कि इस फैसले का असर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक-टोक और X (पूर्व ट्विटर) पर पड़ेगा। इन प्लेटफार्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स पर रोक लगाई जाएगी।

सोशल मीडिया कंपनियों की होगी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यह भी कहा कि यह सोशल मीडिया और टेक कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की उम्र सीमा का पालन किया जाए। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए माता-पिता या बच्चों पर जुर्माना नहीं लगेगा। यह सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें।

इस नए फैसले को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि यह नया कानून इस सप्ताह के अंत तक लागू हो जाएगा और नवंबर में इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस कदम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ सकता है।

सोशल मीडिया के बच्चों पर बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह फैसला स्वागत योग्य माना जा रहा है।

बिजली बिल कम करने के सरल और प्रभावी उपाय, वो आदतें जो बढ़ा सकती हैं आपका बिल

नेशनल डेस्क. बिजली का बिल आमतौर पर हर घर में एक महत्वपूर्ण खर्च होता है, और कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा बिजली बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? हालांकि हम सब कोशिश करते हैं कि बिजली की खपत कम हो, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो अनजाने में हमारे बिल को बढ़ा देती हैं। आजकल स्मार्टफोन से लेकर एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, और गीजर तक, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल हम दिनभर करते हैं। इनमें से कई उपकरणों की खासियत यह है कि यदि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो ये हमारी बिजली की खपत को अनावश्यक रूप से बढ़ा सकते हैं। आइए, जानते हैं कुछ ऐसी आदतों और गलतियों के बारे में, जो न केवल आपके बिजली बिल को बढ़ाती हैं, बल्कि आपके घर में बिजली की खपत को अनावश्यक तरीके से बढ़ा देती हैं।

1. चार्जर को स्विच ऑन करके छोड़ देना

आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर किसी के पास है, और इसके साथ ही चार्जर भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम में से कई लोग चार्जर को बिना स्विच ऑफ किए, सिर्फ प्लग में लगा कर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी आदत से आपकी बिजली की खपत बढ़ सकती है? यह बात सच है कि जब आप चार्जर को स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, तो उससे भी बिजली की खपत होती है। भले ही आपका फोन चार्ज हो चुका हो या चार्जर का उपयोग नहीं हो रहा हो, अगर चार्जर स्विच ऑन रहता है और प्लग में लगा होता है, तो यह लगातार बिजली की खपत करता रहता है। इसे तकनीकी रूप से *फैंटम पावर* या *आइडल लोड* कहा जाता है। इसके कारण बिना किसी काम के भी बिजली खपत होती रहती है, जो आपके बिल को बढ़ाती है।

कितनी खपत होती है?

यदि चार्जर स्विच ऑन करके लगा रहता है, तो यह 0.1 से 0.4 यूनिट तक बिजली की खपत कर सकता है, जो बहुत अधिक नहीं लगता, लेकिन जब यह आदत हर दिन की हो, तो महीनों में यह खपत काफी बढ़ जाती है। अगर अन्य कोई डिवाइस भी स्विच ऑन करके रखा है, तो उसकी बिजली खपत भी इसी तरह बढ़ती रहती है।

2. फास्ट चार्जिंग के कारण बिजली का अधिक उपयोग

आजकल अधिकांश स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग की सुविधा होती है। ये चार्जर मिनटों में फोन को पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फास्ट चार्जिंग चार्जर सामान्य चार्जर के मुकाबले ज्यादा बिजली खपत करते हैं। जब आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बिजली की खपत भी औसतन दोगुनी हो सकती है, क्योंकि ये तेज़ी से ज्यादा पावर खींचते हैं।

क्या करें?

अगर आप अपनी बिजली की खपत को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल कम से कम करें। सामान्य चार्जर का इस्तेमाल करें, जिससे बिजली की खपत कम होगी।

3. स्विच ऑन करके छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

आपने देखा होगा कि हम कई बार टीवी, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, और अन्य उपकरणों को स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं, जबकि उनका उपयोग नहीं हो रहा होता। यह भी एक आम गलती है, जो अनजाने में आपकी बिजली की खपत को बढ़ा देती है। इन उपकरणों को अगर स्विच ऑन किया गया हो और वे यूज में न हो तो भी वे बिजली खा रहे होते हैं। इसे *स्टैंडबाय पावर* कहते हैं।

कितनी खपत होती है?

स्विच ऑन करके छोड़ने से इन उपकरणों से लगातार कम बिजली की खपत होती रहती है। यह खपत दिनभर होती रहती है, और अंततः यह आपके बिल में जुड़कर बड़ा रूप ले सकती है। कुछ डिवाइसों में यह खपत इतनी अधिक हो सकती है कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन अगर ये आदतें नियमित हो जाएं तो अंततः आपका बिजली बिल बढ़ सकता है।

4. एयर कंडीशनर और हीटर का गलत इस्तेमाल

गर्मियों में एयर कंडीशनर (एसी) और सर्दियों में गीजर और हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन इन उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल न करना भी आपके बिजली बिल को बढ़ा सकता है।

एसी का सही तरीके से उपयोग

एसी का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करें कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद हो। जब कमरे के दरवाजे खुले रहते हैं, तो एसी की ठंडी हवा बाहर चली जाती है और एसी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा, एसी के तापमान को बहुत कम रखने से भी बिजली की खपत बढ़ती है। तापमान को 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, क्योंकि यह आदर्श तापमान होता है।

गीजर और हीटर

सर्दियों में गीजर और हीटर का अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका भी अधिक समय तक चलाना अनावश्यक बिजली खपत को जन्म देता है। गीजर को सिर्फ उतनी देर तक चलाएं जब तक पानी गर्म न हो जाए, और फिर उसे स्विच ऑफ कर दें।

5. बिजली बचाने के कुछ आसान तरीके अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल कम आए, तो आपको कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे, जिनसे आपकी बिजली की खपत कम हो सकती है

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569